जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष

स्पेशल स्टोरी पेज 26-47

वर्ष: 7 अंक: 07

1-15 अक्टूबर, 2026 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

भारत का विजन बना वैश्विक मिशन

भारत ने 'मानवता प्रथम, जन-केंद्रित विकास' की भावना से विश्व बंधुत्व का नया अध्याय रचते हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (2026) में दिया संदेश-समग्र विकास वही है, जो जन-जन तक पहुंचे...

हमें फॉलो करें @NISPIBIndia

भारतीय वायु सेना दिवस 94वीं वर्षगांठ (8 अक्टूबर 2026)

'वीरता और पराक्रम का प्रतीक'

भारतीय वायु सेना

भारतीय वायु सेना हर नागरिक के लिए गर्व का प्रतीक है। देश की सुरक्षा हो या किसी आपदा में लोगों की जान बचाना, हमारे जांबाज जवान हमेशा पूरे साहस और निष्ठा के साथ आगे रहते हैं। इतना ही नहीं, अपनी शक्ति और हर चुनौती का सामना करने की तत्परता के बूते इस बल ने हमेशा राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। उत्कृष्ट सेवा और बलिदान के दम पर आकाश क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर हर देशवासियों को है गर्व...

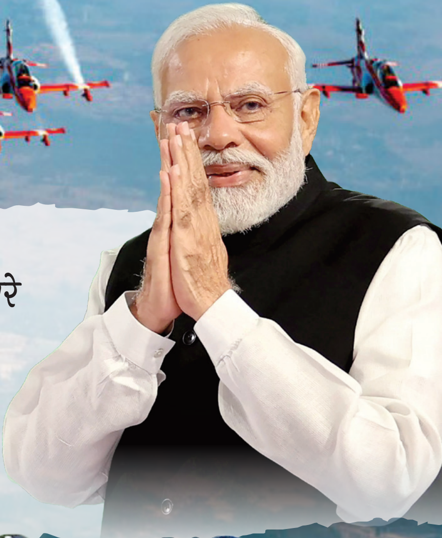

"भारतीय वायु सेना वीरता, अनुशासन और सटीकता का प्रतीक है। उन्होंने हमारे आकाश की सुरक्षा में सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। उनकी प्रतिबद्धता, पेशेवर कौशल और अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

न्यू इंडिया
समाचार

वर्ष: 7, अंक: 07 I 1-15 अक्टूबर, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
सत्यम सिंह
अनिल कुमार

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

भारत के नेतृत्व में मानवता की मिसाल बना ब्रिक्स 2026

आवरण कथा

भारत पहले दिन से ब्रिक्स की कहानी का हिस्सा रहा है और आज पृथ्वी पर हर दूसरा व्यक्ति किसी ब्रिक्स देश में रहता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने ब्रिक्स की यात्रा के 20 वर्ष का उत्सव मनाया। भारत ने 2026 में चौथी बार अध्यक्षता संभाली और 'नई दिल्ली घोषणापत्र' के साथ ब्रिक्स को दी है एक नई, अधिक प्रभावी मानवीय दिशा... | 6-25

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी : सुशासन के 25 वर्ष

निर्णय, चुनौतियों के बीच बदलाव की यात्रा

सुशासन के अपने मॉडल से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब 12 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र को दे रहे हैं नई दिशा... गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ली थी, तब से अनवरत जारी सेवा, समर्पण की उनकी इस यात्रा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट... | 26-47

यूपीआई... एक सभ्यता की कहानी
पीएम मोदी ने मुंबई में 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' का किया उद्घाटन | 48-49

'फ्रेट कॉरिडोर' विकसित होते भारत की जीवनरेखा
पीएम मोदी ने गुजरात को दी 35,000 करोड़ रुपये सौगातें | 50-51

असली ताकत... ज्ञान से जागरूकता और जागरूकता से बदलाव
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को पीएम मोदी ने दिया मंत्र | 52-53

रेल कनेक्टिविटी का विस्तार, ईपीएफओ की वेतन सीमा अब 25 हजार
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय | 54-55

स्पेस एक्सप्लोरेशन का मंत्र टकराव नहीं... सहयोग
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन | 56

'नशामुक्त भारत' का संकल्प, 2029 तक होगा साकार
गृह मंत्री अमित शाह बोले- 2029 तक 'नशामुक्त भारत' होगा देश | 57

भारत की प्राचीन प्रतिभा, फ्रांस की आधुनिक इंजीनियरिंग का संगम
पीएम मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर का किया लोकार्पण | 58-59

व्यक्तित्व : तिरुप्पुर कुमारन
जिन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया राष्ट्रीय ध्वज | 60

एसआरसीसी शताब्दी समारोह

140 करोड़ भारतीय मिलकर...
भारत को बनाएंगे विकसित और आत्मनिर्भर

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मिलकर भारत को बनाएंगे विकसित और आत्मनिर्भर... | 4-5

प्रकाशक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. **ईमेल- response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812**

संपादक की कलम से...

भारत की अगुवाई में ब्रिक्स का नया अध्याय

सादर नमस्कार

ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ पर भारत द्वारा चौथी बार इस समूह की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक अवसर बनकर सामने आई। ब्रिक्स, प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। विश्व की ग्यारह उभरती अर्थव्यवस्थाएं यहां ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करती हैं। ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का भी यह एक प्रभावी माध्यम बन गया है।

'रेजिलिएंस, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण' के विषय पर आधारित इस सम्मलेन में भारत ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से रखा। जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत संतुलित, समावेशी, विकासोन्मुख एवं जन केंद्रित दृष्टिकोण रखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्यों के बीच सहमति बनाने में सफल रहा।

भारत ने इस मंच को सरकारों की सीमाओं से आगे बढ़ाकर आम नागरिकों, किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचाया है। देश के 30 से अधिक शहरों में आयोजित 400 से अधिक बैठकें इस बात का प्रमाण हैं कि भारत ने 'जन-केंद्रित' और 'मानवता प्रथम' दृष्टिकोण को केवल नारा नहीं, बल्कि कार्यशैली बनाया।

12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस यात्रा का शिखर बिंदु रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शासन सुधार पर बल देते हुए 'पिरामिड ऑफ प्रिविलेज' को 'प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप' में बदलने का आह्वान किया। सर्वसम्मति से पारित नई दिल्ली घोषणापत्र में आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, यूएनएससी सुधार और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

भारत की यह अध्यक्षता केवल एक कूटनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि वैश्विक बहुध्रुवीयता की दिशा में एक ठोस कदम है और यही इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। साथ ही, यह एक सुखद संयोग है कि जब ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे भारत ने दुनिया को मानवता का संदेश दिया है, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन यात्रा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह 25 वर्ष की यात्रा भी इस अंक की विशेष रिपोर्ट बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में राष्ट्र ध्वज को नीचे नहीं गिरने देने वाले तिरुप्पुर कुमारन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वायु सेना दिवस और बैक कवर पर 15 अक्टूबर को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र के नमन पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है पत्रिका

मुझे नियमित रूप से ईमेल पर न्यू इंडिया समाचार पत्रिका मिलती है। यह पत्रिका सरकार की पहल, योजनाओं और करेंट अफेयर्स के बारे में जानकारी पहुंचाने का एक बहुमूल्य माध्यम है। यह छात्रों, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

nikhil4249@gmail.com

विकास और परिवर्तनकारी कार्यों की मिलती है जानकारी

मैं न्यू इंडिया समाचार की पूरी संपादकीय टीम की दिल से तारीफ करता हूं। यह बहुत जानकारी देने वाला और काम का पब्लिकेशन है। एक नियमित पाठक होने के नाते, मुझे यह पत्रिका पूरे भारत में हो रहे जरूरी विकास और परिवर्तनकारी कार्यों की जानकारी की एक कीमती माध्यम लगती है।

michaelbks@gmail.com

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और लेखन कार्यों में मिलती है मदद

मैं कर्नाटक के बागलकोट जिले का रहने वाला एक छात्र और लेखक हूं। मैं अपनी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और लेखन कार्यों के लिए 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका पढ़ता रहता हूं। यह एक बेहतरीन पत्रिका है जिसमें ढेर सारी जानकारी रहती है।

rahimanpoetry@gmail.com

मिलती है बहुत सारी जानकारी

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका बहुत ही अच्छी है। मैं इसका हर अंक पढ़ता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और विदेश नीति के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूं। मैं इसको ऑनलाइन पढ़ता हूं। इसमें मुझे बहुत जानकारी मिलती है।

ashishprabhatmishra@gmail.com

भारत के विकास, योजना और बदलते स्वरूप की मार्गदर्शिका

मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। इस दौरान मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के बारे में पता चला। मुझे अहसास हुआ कि यह पत्रिका नहीं बल्कि भारत के विकास, योजनाओं और बदलते स्वरूप की मार्गदर्शिका है। यह पत्रिका पाठकों के लिए ज्ञान का खजाना है।

सुनील कुमार बोहरा

bohramadawas@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

140 करोड़ भारतीय मिलकर...

भारत को बनाएंगे विकसित और आत्मनिर्भर

भारत का तेज विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था इस बात का सबूत है कि देश अब सुस्ती छोड़कर तेजी से फैसले लेने लगा है। वैश्विक अस्थिरता के बीच देश की 7.8% विकास दर आर्थिक मजबूती का प्रमाण है। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 100 वर्ष पूरे होने पर 5 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मिलकर भारत को बनांएगे विकसित और आत्मनिर्भर...

जब कोई संस्थान अपने 100 वर्ष पूरे करता है, तो वह अनगिनत उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर बन जाता है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) की 100 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियां देश और शिक्षा जगत दोनों के लिए गौरवपूर्ण है। दरियागंज की एक छोटी सी इमारत से शुरू होकर एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बनने तक की कॉलेज की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसने कई पीढ़ियों के भविष्य को संवारा है। आज इस कॉलेज के नाम से एक अलग ही गौरव महसूस होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 'आज भी डीयू में सिर्फ यह कह देना ही अपने आप में एक गर्व का विषय है कि आप एसआरसीसी से हैं।'

कॉलेज की समृद्ध विरासत की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां के छात्रों ने कई क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर संस्थान का नाम रोशन किया है। स्वर्गीय अरुण जेटली और संजीव सान्याल जैसे जाने-माने पूर्व छात्रों के साथ काम के अपने निजी अनुभवों को याद करते हुए कहा कि इस कॉलेज से पढ़े लोग कलाकार, राजनेता और जज बनकर देश सेवा कर रहे हैं।

अतीत की चुनौतियों की तुलना आज की उपलब्धियों से करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को परास्त कर दिया गया है, सशस्त्र बल अब दुश्मनों के घर में घुसकर करारा प्रहार कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक शांति बहाल हो चुकी है। आज पूरा विश्व भारत की नीतिगत गतिशीलता और सबसे तेजी से

आयातक से निर्यातक बना...

'मेक इन इंडिया' पहल की उपलब्धियों ने देश को बड़े आयातक से दुनिया का प्रमुख निर्यातक बनाने में सफलता अर्जित की है। देश का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, वहीं स्वदेशी रक्षा उत्पादन करीब 2 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 2013-14 में जहां रक्षा निर्यात महज 600-700 करोड़ रुपये था, वहीं आज यह बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

पक्के और अटल संकल्प...

युवा शक्ति और 140 करोड़ देशवासियों की क्षमता पर अटूट भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रोडमैप सामने रखा। आने वाले समय के बड़े लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को कृषि निर्यात का ग्लोबल हब बनाना है। अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करना है और ओलंपिक खेलों की मेजबानी भी करनी है। पीएम मोदी ने कहा कि और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हमारे पक्के और अटल संकल्प हैं।

एसआरसीसी के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मेट्रो रेल की सवारी कर पहुंचे पीएम मोदी, बच्चों से बातचीत की।

भारतीय दुनिया को करे लीड...

21वीं सदी के युवाओं की महत्वाकांक्षी सोच का ही नतीजा है कि देश के युवा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न जैसे क्षेत्र में विश्व में अग्रणी होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को पिछली पीढ़ियों से भी बड़े सपने देखने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब भारतीय दुनिया की दिग्गज कंपनियों की कमान संभाल रहे हैं, तो फिर भारतीयों की बनाई कंपनियां पूरी दुनिया को लीड क्यों नहीं कर सकतीं?

> *मुझे विश्वास है...हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे...आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी-जान लगा देता हूं।*
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में सराहना कर रहा है। पश्चिम एशिया के युद्ध और वैश्विक व्यापारिक बाधाओं के बीच 7.8 प्रतिशत की तिमाही विकास दर हासिल करना भारत की आंतरिक क्षमता को दर्शाता है।

आलोचकों को इन आंकड़ों से दिया जवाब

आलोचना करने वालों को जवाब देने के लिए अर्थव्यवस्था के ठोस आंकड़े प्रस्तुत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कुल वाहनों की बिक्री में 20 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया, जिसमें दोपहिया वाहनों में 20% और तिपहिया वाहनों में लगभग 30% की बढ़त शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि स्टील और सीमेंट की खपत में 8% की बढ़ोतरी यह साबित करती है कि निर्माण, आवास और व्यावसायिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। मार्च 2014 तक देश की आधी से ज्यादा आबादी के पास बैंक खाते तक नहीं थे, जबकि आज जन-धन योजना के जरिए करीब 60 करोड़ नागरिक बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं। ■

पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भारत के नेतृत्व में मानवता की मिसाल बना ब्रिक्स 2026

भारत पहले दिन से ब्रिक्स की कहानी का हिस्सा रहा है। आज पृथ्वी पर हर दूसरा व्यक्ति किसी ब्रिक्स देश में रहता है। यह समूह दुनिया की लगभग 50% आबादी, 40% जीडीपी और 25% से अधिक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। बीते 20 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था ढाई गुना बढ़ी, जबकि ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी साढ़े चार गुना बढ़ी है। इस वर्ष 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने ब्रिक्स की यात्रा के 20 वर्ष का उत्सव मनाया। 2026 में चौथी बार अध्यक्षता संभालते हुए भारत ने 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण' की थीम दी। यह वही मंत्र है जो बीते 12 वर्षों से भारत की आर्थिक नीति का आधार है। बढ़ते व्यापार अवरोधों के बीच भारत आर्थिक सेतु और भरोसे का नाम बना है तो 'नई दिल्ली घोषणापत्र' के साथ ब्रिक्स को दी है एक नई, अधिक प्रभावी मानवीय दिशा...

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

नया भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ग्रोथ और स्थिरता का भरोसा दे रहा है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, तो भारत आर्थिक सेतु बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र हो या जी-20 या अन्य प्रभावी समूह, भारत आज वैश्विक संस्थाओं की अध्यक्षता करते हुए वसुधैव कुटुंबकम् की भावना के साथ दुनिया को नया आकार, नई दिशा दे रहा है। इसी कड़ी में ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर हमारा भविष्य साझा है, तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। भारत के विजन का ही परिणाम है कि आज ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन- 2026 ने दुनिया को चुनौतियों के समाधान का मानवीय दृष्टिकोण दिया है।

आज जब दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वह जलवायु संकट हो, ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान हो या बहुपक्षीय संस्थाओं की धीमी कार्यशैली, ऐसे समय में ब्रिक्स जैसे मंच की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ब्रिक्स केवल आर्थिक चर्चाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शासन सुधार से लेकर तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु तक सभी क्षेत्र में मजबूत व निर्णायक पहल कर रहा है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और अब तक चार बार- 2012, 2016, 2021 और 2026 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। अपनी हर अध्यक्षता में भारत ने इस मंच को नई दिशा दी है।

> *"भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स को-ऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे entrepreneurs, farmers, researchers, women, youth और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बनें।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

2026 की अध्यक्षता के लिए भारत ने चार स्तंभ तय किए थे- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास (बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंश, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी)। यह सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रखी थी, जो

ब्रिक्स : आधी दुनिया, 40 फीसदी ताकत

सदस्य देश	11 (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात)
ब्रिक्स + भागीदार देश (कुल परिवार)	21 देश
वैश्विक जनसंख्या में हिस्सेदारी	लगभग 50%
वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी	लगभग 40%
वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी	लगभग 25 %
पिछले 20 वर्षों में वैश्विक जीडीपी वृद्धि	लगभग ढाई गुना
इसी अवधि में ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी वृद्धि	लगभग साढ़े चार गुना
भारत की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें/कार्यक्रम	400 से अधिक
इन बैठकों की मेजबानी करने वाले भारतीय शहर	30 से अधिक
ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन बैठक (भारत, 2026) में भागीदार महिला व्यापार नेता	करीब 200

जन-केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण पर आधारित है। इसी सोच को भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदला। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक लचीलेपन को मजबूत करने से लेकर डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी नई तकनीकों को साझा करने पर जोर दिया। भारत की अध्यक्षता के लिए बनाया गया ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो (प्रतीक चिन्ह) भी इसी भावना का प्रतीक है। इसमें फूल की पंखुड़ियां सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के जीवंत रंगों को दर्शाती हैं, जो उनकी सामूहिक ताकत और एकता को उजागर करती हैं। बीच में बना 'नमस्ते' भाव भारत की गर्मजोशी, सम्मान और सामंजस्यपूर्ण सहयोग की भावना को दर्शाता है, जबकि लोगो में ब्रिक्स के तीन मुख्य स्तंभ- राजनीतिक-सुरक्षा सहयोग, आर्थिक-वित्तीय साझेदारी और लोगों के बीच आपसी संपर्क को भी सूक्ष्मता से दर्शाया गया है।

ग्यारह देश, एक मंच ऐसे बना ब्रिक्स

ब्रिक्स दुनिया के 11 प्रमुख उभरते बाजारों और विकासशील देशों का समूह है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। यह समूह वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व

के समकालीन मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच के रूप में काम करता है। इस मंच की नींव 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर हुई पहली ब्रिक (BRIC) विदेश मंत्री बैठक में पड़ी थी। हालांकि 'ब्रिक' (BRIC) संक्षिप्त नाम वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर 'The World Needs Better Economic BRICs' में गढ़ा गया था। इकोनॉमेट्रिक एनालिसिस के आधार पर इस शोध-पत्र में अनुमान लगाया गया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन अगले पांच दशकों के दौरान विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। इन देशों की बढ़ती आर्थिक शक्ति और तीन महाद्वीपों में फैली उनकी विशाल भौगोलिक पहुंच ने उनके उभरते वैश्विक महत्व को रेखांकित किया। इसके बाद ब्रिक की अवधारणा एक औपचारिक समूह के रूप में विकसित हुई। वर्ष 2006 में इसके गठन के तीन साल बाद, 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ।

"आज जब दुनिया में trade barriers बढ़ रहे हैं, भारत economic bridges बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। BRICS में भी हमारी एप्रोच यही है, बैरियर को कम करना और बिजनेस के लिए अवसर बढ़ाना।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल करने पर सहमति बनी और 2011 में सान्या शिखर सम्मेलन से यह समूह दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद औपचारिक रूप से 'ब्रिक्स' बन गया।

बीते तीन वर्षों में इस परिवार का विस्तार तेजी से हुआ है।

टाइमलाइन : बीस साल का सफर, भारत की चार पारियां (2006-2026)

2006	ब्रिक की स्थापना	न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर पहली ब्रिक विदेश मंत्री बैठक
2009	पहला शिखर सम्मेलन	रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित
2011	ब्रिक्स का जन्म	दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से ब्रिक, ब्रिक्स बना (सान्या शिखर सम्मेलन)
2012	भारत की पहली अध्यक्षता	चौथा शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली- विषय: 'वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए ब्रिक्स साझेदारी' दिल्ली घोषणा अपनाई गई
2016	भारत की दूसरी अध्यक्षता	8वां शिखर सम्मेलन, गोवा- विषय: 'जवाबदेह, समावेशी और सामूहिक समाधान का निर्माण' गोवा घोषणा व बिम्सटेक आउटरीच
2021	भारत की तीसरी अध्यक्षता	13वां शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली विषय: 'ब्रिक्स@15: निरंतरता, समेकन और सर्वसम्मति के लिए सहयोग' नई दिल्ली घोषणा
2024	विस्तार का पहला चरण	मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पूर्ण सदस्य बने
2025	विस्तार का दूसरा चरण	इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बना, 10 देश भागीदार देश बने, रियो डी जेनेरियो में 17वां शिखर सम्मेलन
2026	भारत की चौथी अध्यक्षता (ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ)	18वां शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली विषय: 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण' नई दिल्ली घोषणापत्र (140 पैराग्राफ) अपनाया गया
2027	आगामी अध्यक्षता	चीन को अध्यक्षता और 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई

जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसके पूर्ण सदस्य बने और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी इस सूची में जुड़ गया। इसी साल बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भागीदार देशों के रूप में ब्रिक्स परिवार का हिस्सा बने। यानी 20 वर्ष के भीतर चार देशों से शुरू हुआ यह समूह आज 21 देशों के विशाल परिवार में बदल चुका है। यह एक ऐसा विस्तार है जो इस मंच की विश्वसनीयता, महत्व और आकर्षण को दर्शाता है।

संघर्षों के बीच सेतु बना भारत

2026 का साल ऐसे समय में आया जब दुनिया कई मोर्चों पर तनाव से जूझ रही थी। एक ओर पश्चिम एशिया में संघर्ष, यूक्रेन-रूस तनाव की छाया तो दूसरी ओर व्यापार में बाधाओं का बढ़ता जाल और बहुपक्षीय संस्थाओं पर घटता भरोसा। ऐसे माहौल में 11

अलग-अलग सभ्यताओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं और आर्थिक हितों वाले देशों को एक मंच पर लाकर आम सहमति तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। भारत ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 18वें शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स आज अपने 'कमिंग ऑफ एज' के क्षण में है, जैसे मानवीय जीवन में 20 साल की उम्र परिपक्वता और जिम्मेदारी का नया अध्याय शुरू करती है, वैसे ही ब्रिक्स भी अब सपनों के साथ जिम्मेदारियां जोड़ने के चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि ब्रिक्स की ताकत इस बात में है कि यह किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच पर आधारित है। सदस्य देश आपसी सम्मान के साथ आम सहमति से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस सोच की झलक नई दिल्ली घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। एक ओर जहां आतंकवाद के खिलाफ बेहद स्पष्ट और सख्त

> *हमारा भविष्य साझा है, इसलिए उस भविष्य को आकार देने का अधिकार भी साझा होना चाहिए - आवाज उठाने से लेकर प्रभाव छोड़ने तक और विशेषाधिकार से लेकर साझेदारी तक।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

भाषा अपनाई गई। अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए घोषणापत्र में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और दोहरे मापदंड न अपनाने का आह्वान किया गया, वहीं दूसरी ओर गाजा, लेबनान, सीरिया और सूडान

भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

2026 : 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन- 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत ने मेजबानी की। थीम-'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण' रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में रियो शिखर सम्मेलन के दौरान इस सोच को सामने रखा था जो 'मानवता प्रथम' और जन-केंद्रित सोच पर आधारित है। 2026 में ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे हुए।

- इस घोषणा पत्र में 140 बिंदु शामिल किए गए। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर ब्रिक्स टास्क फोर्स, ब्रिक्स कनेक्ट, ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज, जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौता के साथ ही नया विकास बैंक जैसे प्रमुख बिंदु शामिल रहे।

2021 : 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन- 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल आयोजित हुआ। इसकी थीम -'ब्रिक्स @15 : निरंतरता, मजबूती और सहमति के लिए सहयोग' रही।"

- इस घोषणा पत्र में बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, आतंकवाद से मुकाबला, **SDGs** के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत ने ब्रिक्स की कार्यप्रणाली को सरल बनाया और डिजिटल हेल्थ समिट तथा पहली जल मंत्रियों की बैठक जैसे नए मंच शुरू किए।

2016 : 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-15-16 अक्टूबर 2016 को गोवा में हुआ। इसकी थीम -'जवाबदेह, समावेशी और सामूहिक समाधान का निर्माण' थी।

- गोवा घोषणा पत्र और कार्ययोजना में न्यू डेवलपमेंट बैंक के काम शुरू करने और अक्षय ऊर्जा के लिए दिए गए पहले कर्ज का स्वागत किया गया तो संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया, ताकि विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ सके।

2012 : चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 29 मार्च 2012 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम -'वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए ब्रिक्स की साझेदारी' रही।

- इसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था में असमान सुधार, देशों पर बढ़ते कर्ज के जोखिम और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सभी सदस्य देशों के विविध राष्ट्रीय दृष्टिकोणों का सम्मान करते हुए संतुलित भाषा तैयार की गई। यह भारत की कूटनीतिक परिपक्वता का ही परिणाम था कि इतने विविध हितों वाले देश एक साझा घोषणापत्र पर सहमत हो सके।

रियो डी जेनेरियो में 2025 के शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी सोच को रेखांकित करते हुए कहा था कि बीसवीं सदी में बने वैश्विक संगठन इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें एक बहुध्रुवीय व समावेशी विश्व व्यवस्था

के अनुरूप सुधरना होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स का विस्तार यह साबित करता है कि यह समूह समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता रखता है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए व्यापार, स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु जैसे व्यावहारिक क्षेत्रों में ठोस पहल कीं, ताकि दुनिया की अस्थिरता के बीच ब्रिक्स सहयोग और भरोसे की एक मिसाल बनकर उभरे।

नई दिल्ली घोषणापत्र: बदलाव का 140 सूत्रीय खाका

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया 'नई दिल्ली घोषणापत्र', जिसका विषय था 'सक्षमता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण'। ब्रिक्स के दो दशकों के अनुभव और भारत की अध्यक्षता के दौरान हुए 400 से अधिक बैठकों के निचोड़ को समेटे हुए है। यह 140 पैराग्राफ का व्यापक दस्तावेज बना है, जिसमें वैश्विक शासन सुधार से लेकर स्वास्थ्य, कृषि, तकनीक, जलवायु और संस्कृति तक हर क्षेत्र को समेटा गया है। घोषणापत्र में सबसे उल्लेखनीय बिंदु रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर सदस्य देशों की एकजुटता। चीन और रूस ने स्थायी सदस्य के रूप में भारत और ब्राजील की सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में अधिक भूमिका निभाने की आकांक्षाओं के लिए अपने समर्थन को दोहराया। घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि 20वीं सदी में बनी वैश्विक संस्थाएं आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करतीं और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं में तत्काल सुधार जरूरी है।

> *इनोवेशन के अंतर्गत BRICS Incubator Network हमारे स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर को आपस में जोड़ेगा। छोटे उद्यमों को नॉलेज, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए, BRICS एमएसएमई को-ऑपरेशन पोर्टल की पहल की है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

आतंकवाद पर घोषणापत्र की भाषा बेहद स्पष्ट रही। सदस्य देशों ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख स्तंभ

लचीलापन

- वैश्विक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, स्वास्थ्य चुनौतियों और जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत लचीलेपन को मजबूत करना।

नवाचार

- प्रभावी सेवा वितरण और भविष्य के लिए तैयार विकास को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, एआई और ज्ञान साझा करने जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को तैनात करना।

सहयोग

- नीति समन्वय, विकास वित्त, व्यापार सुविधा, वैश्विक संस्थागत शासन में सुधार और जन-केंद्रित साझेदारी के माध्यम से ब्रिक्स सदस्यों के बीच बहुपक्षीय जुड़ाव को गहरा करना।

सतत विकास

- राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप जलवायु कार्रवाई, हरित वित्त, ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास की दिशा में सामूहिक प्रयासों में तेजी लाना।

ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो

ब्रिक्स 2026 का लोगो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल है। इसमें फूल की पंखुड़ियों के रंग ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के जीवंत रंगों को दर्शाते हैं। यह देशों की एकता और सामूहिक ताकत का प्रतीक है। बीच में 'नमस्ते' का भाव भारत की पुरानी परंपरा, अपनापन, सम्मान और मिल-जुलकर काम करने की भावना को दर्शाता है। इस लोगो में तीन मुख्य स्तंभों को भी दर्शाया गया है...

- राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग
- आर्थिक और वित्तीय साझेदारी
- संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क-सहयोग

सभ्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर घोषणापत्र ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के दूसरे 'स्वर्णिम दशक' में प्रवेश करने का स्वागत किया और मई 2026 में मॉस्को में आयोजित इसकी 11वीं वार्षिक बैठक का उल्लेख किया। भारतीय अध्यक्षता में तैयार किए गए ब्रिक्स-एनडीबी नॉलेज पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ, जो सदस्य देशों के विकास अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को एक साथ लाता है। सीमा-पार भुगतान को तेज, सस्ता और सुरक्षित

देश के 30 शहरों में 400 से अधिक बैठकों में ब्रिक्स मंथन

भारत की अध्यक्षता में **BRICS** के सदस्य राष्ट्रों और संगठनों की भागीदारी वाले शिखर सम्मेलन के दौरान, उससे पहले देश के 30 शहरों में हुई 400 बैठकों में निकले निष्कर्षों और सहमति को आगे बढ़ाया गया। राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग तथा सांस्कृति एवं लोगों के बीच संपर्क ही सहयोग के तीन प्रमुख स्तंभ रहे। भारत की अध्यक्षता के दौरान **BRICS** के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में 50 से अधिक परिणाम हासिल किए गए। कई परिणाम प्लेटफॉर्म, फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस के रूप में तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य **BRICS** के तीसरे दशक में भी निरंतर सहयोग और भागीदारी को आगे बढ़ाना है। बैठकों में जो सहमति बनी, उसे ब्रिक्स की नई दिल्ली घोषणाओं में शामिल किया गया। नई दिल्ली घोषणा में 140 बिंदु शामिल रहे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण यहां दे रहे हैं। पूरा घोषणा पत्र पढ़ने के लिए **https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl**/41776 लिंक पर क्लिक करें।

BRICS नई दिल्ली घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार** : **UN** सुधार और **Security Council** में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर। चीन और रूस ने भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका की आकांक्षा का समर्थन दोहराया।
- **आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख** : जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। आतंकवाद के सभी रूपों, सीमा-पार आतंकवाद, आतंक वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही गई।
- **Kimberley Process में भारत की अध्यक्षता** : 2026 में **Kimberley Process** की भारत की अध्यक्षता का स्वागत; **BRICS** में अफ्रीकी डायमंड उत्पादक देशों के साथ सहयोग को समर्थन।
- **गिफ्ट सिटी में ब्रिक्स रिस्क लैब** : भारत के प्रस्ताव पर गुजरात के गिफ्ट सिटी **IFSC** में ब्रिक्स रिस्क लैब की मेजबानी पर आगे चर्चा का समर्थन।
- **ग्रोथ-डेवलपमेंट पर ब्रिक्स टास्क फोर्स** : भारत की पहल पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टास्क फोर्स स्थापित, विकास मॉडल, डिजिटल बदलाव, **AI** और विकास वित्त पर सहयोग का मंच।
- **BRICS-NDB नॉलेज पोर्टल** : भारत की अध्यक्षता में **BRICS-NDB** नॉलेज पोर्टल शुरू, विकास अनुभव, श्रेष्ठ प्रथाओं और नीतिगत नवाचारों का साझा मंच।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** : **BRICS** देशों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी और डीपीआई समाधानों के पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव।

बनाने के लिए ब्रिक्स भुगतान कार्य बल के प्रयासों को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर घोषणापत्र में इसे आर्थिक व सतत विकास के लिए एक बड़े अवसर के रूप में स्वीकार किया गया, साथ ही इसकी सुरक्षा, समावेशिता और भरोसेमंद सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया गया। सदस्य देशों ने फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट

- **AI सहयोग :** **AI** को आर्थिक विकास और सतत विकास का महत्वपूर्ण साधन माना, सुरक्षित, समावेशी, विश्वसनीय और सुलभ **AI** के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर। भारत के **AI** इंपैक्ट समिट 2026 का स्वागत।
- **NIMHANS के साथ मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क BRICS** सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेटवर्क के समन्वयक के रूप में **NIMHANS** को शामिल करने का समर्थन; मानसिक स्वास्थ्य पर शोध और नीति सहयोग का मंच।
- **क्रिटिकल मिनरल्स :** क्रिटिकल मिनरल्स के लिए विश्वसनीय, विविधीकृत और रेजिलिएंट सप्लाई चेन और संसाधन-समृद्ध देशों में वैल्यू एडिशन पर जोर।
- **चेन्नई सहमति और विज्ञान रिपॉजिटरी :** चेन्नई सहमति संयुक्त घोषणा का स्वागत, **BRICS** साइंस एंड रिसर्च रिपॉजिटरी तथा **GRAIN Centres** की दिशा में सहयोग।
- **सौर फोटोवोल्टिक सहयोग : BRICS** सोलर फोटोवोल्टिक कोऑपरेशन रोडमैप विकसित करने का समर्थन; तकनीक, वित्त और क्षमता निर्माण में सहयोग।
- **इंडिया सेंटर फॉर ब्रिक्स इंडस्टीयल कंपीटेंसी :** इंडिया सेंटर फॉर ब्रिक्स इंडस्टीयल कंपीटेंसी (**ICBIC**) की स्थापना का स्वागत।
- **BRICS एसएमई फोरम, आगरा :** भारत की अध्यक्षता में पहला **BRICS** एसएमई फोरम, आगरा में आयोजित, एमएसएमई की वित्त और तकनीक तक पहुंच बढ़ाने पर जोर।
- **BRICS इन्क्यूबेटर नेटवर्क : BRICS** इन्क्यूबेटर नेटवर्क की स्थापना का स्वागत और **BRICS** स्टार्टअप इनोवेशन फंड पर आगे विचार।
- **कर सहयोग :** भारत की अध्यक्षता में **BRICS** टैक्स अथोरिटीज के सहयोग के लिए नए वर्किंग ग्रुप; टैक्स सपोर्ट नेटवर्क और टैक्स क्रॉस-लर्निंग लैब पहलें।
- **महिलाओं की डिजिटल क्षमता का निर्माण :** ब्रिक्स वीमेन डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग गाइडलाइंस का स्वागत, भारत की पहल पर महिलाओं के सशक्तीकरण की श्रेष्ठ प्रथाओं का डिजिटल रिपॉजिटरी।
- **पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान :** भारत की पहल पर पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों में अकादमिक सहयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों का स्वागत।
- **शिक्षा और कौशल :** शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और कार्यबल तैयारी मजबूत करने पर जोर, ब्रिक्स-**TCA** को सहयोग का मंच माना।
- **ब्रिक्स कनेक्ट :** ब्रिक्स कनेक्ट को क्षमता निर्माण, रोजगार-योग्यता और नई तकनीकों/कौशल के लिए अपनाया गया; दूरस्थ रोजगार के लिए अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहल।
- **BRICS रिमोट सेंसिंग उपग्रह तारामंडल :** रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन की उपलब्धियों का स्वागत; ब्रिक्स स्पेस काउंसिल और नई स्पेस एजेंसियों को शामिल करने की दिशा में प्रगति।

के सफल आयोजन पर बधाई दी।

सबसे दिलचस्प रहे प्रधानमंत्री मोदी के तीन प्रस्ताव, जो उन्होंने वैश्विक शासन पर सत्र में रखे। उन्होंने वैश्विक शासन ढांचे की तुलना एक ऐसे पिरामिड से की जिसके ऊपरी हिस्से में सत्ता केंद्रित है जबकि निचले हिस्से में वे देश हैं जो फैसलों से प्रभावित तो होते हैं पर उन्हें आकार नहीं दे पाते। उन्होंने इस 'पिरामिड ऑफ प्रिविलेज'

- **सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर क्राइम** : सुरक्षित, स्थिर, इंटरऑपरेबल **ICT** वातावरण पर जोर, साइबर अपराध के विरुद्ध **UN** कन्वेंशन को लागू करने की दिशा में सहयोग।
- **साइबर सुरक्षा और डीपफेक** :साइबर अपराध, गलत सूचना, भ्रामक सूचना, नफरती भाषण और डीपफेक जैसी डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग।
- **स्थानीय मुद्रा में भुगतान** : ब्रिक्स देशों के बीच सीमा-पार भुगतान को तेज, कम लागत वाला, सुरक्षित और सुलभ बनाने के प्रयास, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान पर चर्चा जारी।
- **निपटान और डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर** सेटलमेंट और डिपॉजिटरी प्रणालियों पर तकनीकी कार्यशाला के बाद ज्ञान और अनुभव साझा करने पर सहयोग।
- **MSMEs के लिए इनवॉइस डिस्काउंटिंग** जयपुर कंसेंसस के तहत ब्रिक्स में इनवॉइस डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म स्थापित करने का अध्ययन, **MSMEs** को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं** : ब्रिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को लचीला और समावेशी बनाने के साथ ही विकासशील देशों को उच्च-मूल्य खंडों में आगे बढ़ाने पर जोर।
- **ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज** : ब्रिक्स में ग्रेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/बीआरआईसीएस ग्रेन एक्सचेंज स्थापित करने की पहल पर आगे चर्चा, कृषि उत्पादों और वस्तुओं तक विस्तार की संभावना।
- **ब्रिक्स एग्रिन** : कृषि इनपुट, आनुवंशिक संसाधनों और सूचना के लिए ब्रिक्स **AGRIN** स्थापित करने पर सहमति; बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच का स्वागत।
- **ऊर्जा सुरक्षा** : ऊर्जा सुरक्षा, स्थिर ऊर्जा बाजार और लचीले ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर; ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन का स्वागत।
- **स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण** : ब्रिक्स स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी स्टोरेज मार्गदर्शक सिद्धांतों का स्वागत, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पहल।
- **जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौता** : पेरिस समझौते के पूर्ण क्रियान्वयन, अनुकूलन, हानि-क्षति तथा विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर जोर।

को 'प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप' में बदलने का आह्वान करते हुए प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम-निर्माण, इन तीन आधारों पर एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप तैयार करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ब्रिक्स की निरंतरता बनाए रखने के लिए 'ब्रिक्स कंटिन्यूटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म' का प्रस्ताव भी रखा, ताकि हर साल बदलती अध्यक्षता के बावजूद निर्णयों की निगरानी और क्रियान्वयन बाधित न हो। इसके अलावा उन्होंने समुद्री यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'सीफेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क' बनाने का सुझाव भी दिया। घोषणापत्र के अंत में सदस्य देशों ने 2026 में भारत की अध्यक्षता और नई दिल्ली में हुए सफल आयोजन के लिए भारत सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया और 2027 में अध्यक्षता तथा 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को पूर्ण समर्थन दिया।

- **ब्रिक्स कार्बन मार्केट साझेदारी** : ब्रिक्स कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के माध्यम से कार्बन बाजारों पर सहयोग, क्षमता निर्माण और अनुभव साझा करने का समर्थन।
- **अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस** : भारत की इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस बनाने की पहल का उल्लेख और ब्रिक्स देशों से बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सहयोग का आह्वान।
- **आपदा प्रबंधन** : आपदा जोखिम कम करने के लिए सहयोग; डिजास्टर मैनेजमेंट अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस और जलवायु-लचीली शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वैच्छिक सिद्धांतों का स्वागत।
- **सतत परिवहन** : सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, परिवहन डीकार्बोनाइजेशन और ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना का स्वागत; लॉजिस्टिक्स सप्लाई-चेन कोऑपरेशन फ्रेमवर्क भी शामिल।
- **शहरीकरण मंच** : नई दिल्ली में ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम और मंत्रिस्तरीय घोषणा का स्वागत; ब्रिक्स अर्बन रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क की स्थापना।
- **स्वास्थ्य और क्षय रोग** : सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर सहयोग; टीबी शोध, साझा तकनीक और एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए समर्पित उप-कार्यसमूह की स्थापना।
- **नया विकास बैंक** : **NDB** की भूमिका मजबूत करने, स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण बढ़ाने, वित्त-पोषण स्रोतों में विविधता लाने और ग्लोबल साउथ में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ावा देने पर जोर।
- **भारत की अध्यक्षता और चीन को समर्थन** : ब्रिक्स ने भारत की 2026 अध्यक्षता की सराहना की और नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत का आभार जताया। 2027 की ब्रिक्स अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के लिए चीन को पूर्ण समर्थन दिया।

तीस शहर, चार सौ बैठकें, नौ महीने का महामंथन

1 जनवरी 2026 को अध्यक्षता संभालने के साथ ही भारत ने पूरे साल एक सुनियोजित कैलेंडर के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिक्स सहयोग केवल शिखर सम्मेलन के दो दिनों तक सीमित न रहे, बल्कि हर मंत्रालय, हर क्षेत्र और हर वर्ग तक पहुंचे। साल भर में देश के तीस से अधिक शहरों में चार सौ से ज्यादा बैठकें और कार्यक्रम हुए। इसमें मंत्रिस्तरीय बैठकों से लेकर कार्यशालाओं, मंचों और सम्मेलनों का रूप दिया गया। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले के हफ्तों में हुई मंत्रिस्तरीय बैठकों ने इस अध्यक्षता की दिशा तय कर दी थी। चेन्नई में हुई 14वीं ब्रिक्स विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक में 'चेन्नई घोषणा' को मंजूरी दी गई,

जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक और जैव-तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स विज्ञान एवं अनुसंधान भंडार बनाने पर सहमति बनी। 7 अगस्त को भुवनेश्वर में हुई 13वीं शिक्षा मंत्रियों की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा और बुनियादी साक्षरता सुधारने के साथ ही शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक इस्तेमाल पर सहमति बनी। 18 अगस्त को नई दिल्ली में हुई 12वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने टिकाऊ जीवनशैली, वनीकरण, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और जलवायु अनुकूलन को चार प्राथमिकताओं के रूप में रखा। 21 अगस्त को जयपुर में हुई पर्यटन मंत्रियों की बैठक में 'जयपुर घोषणा' अपनाई गई, जिसमें पर्यटन में तकनीक के इस्तेमाल और सतत पर्यटन पर जोर दिया गया। 22 अगस्त को विशाखापत्तनम में युवा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें प्रतिनिधियों ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण भी किया।

स्वास्थ्य क्षेत्र की चंडीगढ़ में 23 जुलाई को हुई 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जहां सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, तपेदिक उन्मूलन और महामारी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी और निमहान्स (NIMHANS) के समन्वय में मानसिक स्वास्थ्य पर एक नया नेटवर्क बनाने का फैसला हुआ। इंदौर में हुई कृषि मंत्रियों की बैठक में किसान केंद्रित 'ब्रिक्स एग्रीन' (कृषि-इनपुट, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क) मंच बनाने पर सहमति बनी। कोच्चि में महिला मंत्रिस्तरीय बैठक, भोपाल में संस्कृति मंत्रियों की बैठक (जहां 'भोपाल घोषणा' अपनाई गई), नागपुर में परिवहन मंत्रियों की बैठक और आगरा में पहला ब्रिक्स लघु एवं मध्यम उद्यम मंच, इन सभी ने मिलकर यह दिखाया कि भारत की अध्यक्षता कितनी व्यापक और समावेशी रही।

> *टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का weaponization हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में inclusivity पर बल दिया है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026 अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम रहा। इसे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में जहां वैश्विक जीडीपी करीब ढाई गुना बढ़ी है, वहीं ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी साढ़े चार गुना बढ़ी है। यानी

> *हमारा मानना है कि BRICS में विकसित solutions का लाभ केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन्हें ग्लोबल साउथ की आवश्यकताओं के अनुरूप adaptable और accessible बनाना चाहिए।*
>
> **–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ब्रिक्स की आर्थिक ताकत दुनिया की तुलना में करीब दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ी है। उन्होंने भारत के दो लाख से अधिक स्टार्टअप और एक सौ बीस से अधिक यूनिकॉर्न, यूपीआई जैसी डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और 2014 के बाद से करीब 40 देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों का उल्लेख करते हुए ब्रिक्स व्यापार परिषद से आग्रह किया कि वह हर साल व्यापार बाधाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करे, सौ स्टार्टअप को दूसरे बाजारों में विस्तार में मदद करे और व्यवसायों के बीच एक हजार नई साझेदारियां विकसित करे।

मंच से मुलाकात तक, पीएम मोदी की सक्रिय कूटनीति

शिखर सम्मेलन के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कई द्विपक्षीय बैठकों के जरिये भी विश्व नेताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया, जो भारत की अध्यक्षता को और सार्थक बना गया। 12 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 की तियानजिन बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि दोनों पक्षों को पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित, इन तीन 'पारस्परिकताओं' से मार्गदर्शन लेना चाहिए और सीमा क्षेत्रों में शांति व स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास का आधार बताया।

13 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव से मुलाकात कर राजनीतिक, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। इसी दिन युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपेल अलुपो से हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने युगांडा के 'विजन 2040' को भारत के समर्थन की पुष्टि की, जबकि नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेत्तिमा मुस्तफा के साथ बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, कृषि और डिजिटल तकनीक सहित प्रमुख क्षेत्रों

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

में भारत-नाइजीरिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में हुए चीतों के सफल स्थानांतरण का उल्लेख करते हुए दक्षिण अफ्रीका को इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस में शामिल होने का न्योता दिया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये के साथ हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की और प्रधानमंत्री ने इबोला प्रकोप से निपटने में अफ्रीकी संघ के नेतृत्व की सराहना की।

इन सभी बैठकों की एक साझा कड़ी रही- भारत का ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाने और बहुध्रुवीय, समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह। यही वह धागा था जिसने शिखर सम्मेलन के औपचारिक सत्रों को द्विपक्षीय कूटनीति की गर्मजोशी से जोड़ दिया।

इस द्विपक्षीय मुलाकातों के बाद कई नेताओं ने भारत की मेजबानी की सराहना की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने गर्मजोशीपूर्ण आतिथ्य और शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली घोषणापत्र में भी सभी सदस्य देशों ने सामूहिक रूप से 2026 में भारत की अध्यक्षता की सराहना करते हुए नई दिल्ली में 18वें शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति आभार व्यक्त किया।

> *"ग्लोबल साउथ वैश्विक संकटों का सामना करने के मामले में सबसे अग्रिम पंक्ति में है लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पीछे। हमें 'पिरामिड ऑफ प्रिविलेज' को 'प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप' में बदलना होगा।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

नमस्ते की गूंज: संस्कृति से जुड़ा ब्रिक्स परिवार

भारत ने अपनी अध्यक्षता में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी उतना ही महत्व दिया, जितनी आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को। भोपाल में आयोजित 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में अपनाई गई 'भोपाल घोषणा' में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संग्रहालयों-अभिलेखागारों के बीच सहयोग और कलाकारों के लिए एक साझा रजिस्ट्री बनाने जैसी पहलों पर सहमति बनी। इसके साथ ही ब्रिक्स संस्कृति महोत्सव, थिएटर महोत्सव और फिल्म महोत्सव के आयोजन ने सदस्य देशों की सांस्कृतिक विविधता को मंच दिया। बीस साल के ब्रिक्स सहयोग को यादगार बनाने के लिए 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए- 'ब्रिक्सः सहयोग के दो दशक, 2006-2026'। पहला टिकट आपसी

सम्मान और एकजुटता के मंच के रूप में ब्रिक्स के उभरने को दर्शाता है, जबकि दूसरा टिकट भारत की अध्यक्षता के 'मानवता सबसे पहले' और 'जन-केंद्रित' विजन तथा लोगो (प्रतीक चिन्ह) को प्रदर्शित करता है।

इस वैश्विक सम्मेलन के दौरान भारत की ओर से विदेशी मेहमानों की स्थानीय संस्कृति, कला से जुड़े स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। इसमें विशेष रूप से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के तहत तैयार पश्मीना शॉल, वाराणसी का रेशमी ब्रोकेड, कन्नौज का इत्र, राजस्थानी मीनाकारी और खादी उत्पाद जैसे स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।

> *ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब sea lanes सेक्योर हों, supply routes open हों और seafarers safe हों। और इसलिए, भारत freedom of navigation और seafarers की safety का दृढ़ समर्थक है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

युवा जोश, नारी नेतृत्व बना ब्रिक्स का मानवीय चेहरा

भारत की अध्यक्षता की एक बड़ी विशेषता यह रही कि उसने ब्रिक्स सहयोग को सरकारी दायरे से निकालकर आम नागरिकों, खासकर युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाया।

युवाओं की भागीदारी : 22 अगस्त 2026 को विशाखापत्तनम में हुई ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक में शिक्षा, कौशल विकास,

रोजगार और युवा उद्यमिता में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, साथ ही युवाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस मौके पर प्रतिनिधियों ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। यह एक ऐसा प्रतीकात्मक कदम बना जिसने पर्यावरण और भावनात्मक जुड़ाव, दोनों को एक साथ जोड़ा। नई दिल्ली घोषणापत्र में भी ब्रिक्स यूथ काउंसिल और ब्रिक्स यूथ समिट की भूमिका की सराहना करते हुए शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया गया। साथ ही, ब्रिक्स यूथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर हुई प्रगति का भी स्वागत किया गया।

महिला नेतृत्व : कोच्चि में आयोजित ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक महिला-नेतृत्व वाले विकास की परिकल्पना पर केंद्रित रही, जिसमें महिलाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव की प्रेरक शक्ति के रूप में मान्यता दी गई। इस बैठक में ब्रिक्स महिला डिजिटल क्षमता निर्माण दिशानिर्देशों के विकास का स्वागत हुआ। इसके साथ ही ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन (डब्ल्यूबीए) की 2026 की गतिविधियों में भारत में लगभग 200 महिला व्यापार नेताओं ने भागीदारी की, जिसका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए वित्त, बाजार, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास तक पहुंच बेहतर बनाना है।

> *महामारियों, जलवायु आपदाएं और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान ने दिखाया है कि आज के परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में संकट से उबरने की क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दिया है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

युवाओं के जोश और महिलाओं के नेतृत्व की यह मिसाल दिखाती है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स केवल कूटनीति और अर्थशास्त्र का मंच नहीं रहा, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों तक पहुंचा जो इस समूह के असली भविष्य हैं।

निश्चित रूप से भारत सहित चार देशों ने मिलकर 20 वर्ष पूर्व जब ब्रिक का सपना देखा था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह समूह एक दिन दुनिया की आधी आबादी और 40 फीसदी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला मंच बन जाएगा। 2026 में भारत की अध्यक्षता में हुआ 18वां शिखर सम्मेलन इस यात्रा का

12 वर्षों में इन मंचों से दुनिया की मुखर आवाज बना भारत

- **2016:** भारत ने 2016 में **BRICS** की अध्यक्षता की।
- **2018:** भारत ने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लीयर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर(**ITER**) के काउंसिल की 1 जनवरी, 2018 में दो वर्ष के लिए अध्यक्षता संभाली।
- **2018-2020:** भारत **ISA Assembly** के अध्यक्ष के रूप में रहा; फ्रांस सह-अध्यक्ष था।
- **2019:** भारत ने किंबरले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली।
- **2019-2020 - (GFDRR):** भारत ने **Global Facility for Disaster Reduction and Recovery** के **Consultative Group** के सह-अध्यक्ष की भूमिका संभाली।
- **2020-2021:** भारत ने **WHO Executive Board** की अध्यक्षता की; डॉ. हर्षवर्धन **Chair** रहे।
- **2020-2021:** भारत ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की **Governing Body** की अध्यक्षता संभाली।
- **2020-2022: ISA Assembly** के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में भारत और फ्रांस को फिर चुना गया।
- **2021:** भारत ने जनवरी–दिसंबर 2021 तक **BRICS** की अध्यक्षता की।
- **2021:** भारत ने अगस्त 2021 में **UNSC** की अध्यक्षता की।
- **2022:** भारत ने दिसंबर 2022 में **UNSC** की अध्यक्षता की।
- **2022-2023:** भारत ने 17 सितंबर 2022 से 4 जुलाई 2023 तक संघाई को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन(**SCO**) की अध्यक्षता की।
- **2022-2024:** भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का अध्यक्ष रहा।
- **2022-2023:** भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक **G20** की अध्यक्षता की।
- **2023:** भारत ने 2023 में **Wassenaar Arrangement** की **Plenary Chairmanship** संभाली। भारत 2017 में इसका सदस्य बना।
- **2024-2026:** भारत 2024-26 के लिए **ISA Assembly** का **President** है।
- **2024-26:** भारत ने 29 मई, 2024 को पहली बार कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली, कार्यकाल 2024-26 है।
- **2024–2025:** भारत ने जुलाई 2024 में **Asian Disaster Preparedness Centre** की **Chairmanship** संभाली।
- **2026:** भारत ने 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोरल असिस्टेंस के काउंसिल मेंबर स्टेट्स की अध्यक्षता संभाली।
- **2026:** भारत ने 1 जनवरी 2026 को चौथी बार **BRICS** की अध्यक्षता संभाली।

एक निर्णायक पड़ाव सिद्ध हुआ है। यह वह क्षण बन गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'कमिंग ऑफ एज' में कदम बताया। भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स में सपनों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ीं और सामूहिक ताकत को ठोस, व्यावहारिक परिणामों में बदला गया। भारत ने साल भर चली 400 से अधिक बैठकों, दर्जनों घोषणाओं और कई पहल के जरिए यह सिद्ध किया कि ब्रिक्स सहयोग केवल सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों और शोधकर्ताओं तक पहुंच सकता है। आतंकवाद पर स्पष्ट और सख्त रुख, वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मुखर मांग, गाजा-सूडान-सीरिया जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित कूटनीति, और साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा जलवायु सहयोग जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में ठोस पहल। इन सबने मिलकर 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। ब्रिक्स 2026, भारत की अध्यक्षता में, केवल एक सफल शिखर सम्मेलन नहीं बल्कि मानवता के लिए समन्वय, सामंजस्य और सामूहिक जिम्मेदारी की एक अमिट मिसाल बनकर अंकित हो गया है। अब यह जिम्मेदारी 2027 में चीन के पास जाएगी लेकिन जो मानदंड और भरोसा भारत ने इस साल स्थापित किया है, वह आने वाले वर्षों में ब्रिक्स की दशा-दिशा तय करता रहेगा। ■

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी : सुशासन के 25 वर्ष

निर्णय, चुनौतियों के बीच बदलाव की यात्रा

स्वतंत्र भारत के एक गरीब परिवार में जन्में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवा ही संकल्प, आज नए भारत का मूलमंत्र बन चुका है। राष्ट्र को परिवारजन मानकर भारत को नई दिशा देने में जुटे प्रधानमंत्री मोदी का एक ही धर्म है- राष्ट्र प्रथम। उनकी सरकार की एक ही पवित्र पुस्तक है- संविधान। एक ही भक्ति है- भारत भक्ति। एक ही शक्ति है- जन शक्ति। एक ही संस्कार है- 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा व समृद्धि। उनकी सरकार का एक ही मंत्र है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सुशासन के अपने इस मंत्र को पहले 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब 12 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में बढ़ाते हुए राष्ट्र को दे रहे हैं नई दिशा... गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ली थी, तब से अनवरत जारी सेवा, समर्पण की उनकी यात्रा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट...

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर्मठ कार्यकर्ता की भांति मेहनत करते हैं, एक स्टेटसमैन की भांति देश का गौरव बढ़ाते हैं, एक टीम लीडर की भांति देश का नेतृत्व करते हैं, भावुक राजनेता की भांति संवेदनशील फैसले लेते हैं, निडर सेनापति की भांति राष्ट्ररक्षा में अडिग चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। दीपक की लौ की तरह उर्ध्व दिशा में ही सोचते हैं।" सदैव एक सारथी की भूमिका में रहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जब यह बात कही तो उनका संकेत बेहद स्पष्ट था कि राष्ट्र की सेवा यात्रा में इस पड़ाव तक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक जीवन की यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन वे ठहरे नहीं। इसका कारण है कि उन्होंने राजनीति का पाठ भी राष्ट्रनीति की भाषा में पढ़कर उसे अपने जीवन का संस्कार बनाया और सर्वसमावेशी विकास की नई पटकथा तैयार की। न थमना, न थकना, न रुकना, अथक परिश्रम से आगे बढ़ते जाना। नए-नए लक्ष्य निर्धारित करना और अंतिम छोर तक उसे पहुंचाकर विकास की सशक्त गाथा लिखना। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की अलग पहचान है, जिनका खुद का परिवार आज भी सामान्य जीवन जी रहा है क्योंकि उनके लिए 140 करोड़ से अधिक देशवासी ही उनका परिवार है।

इस 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 25 वर्षों की यात्रा को केवल राजनीतिक पदों और चुनावी जीत के क्रम में नहीं देखा जा सकता। यह लगातार बदलती चुनौतियों के बीच लिए गए फैसलों और उनसे निकली नई दिशाओं की कहानी भी है। गुजरात में शुरुआत भूकंप, सूखे, पानी की कमी और सांप्रदायिक हिंसा जैसी गंभीर चुनौतियों के बीच हुई। आगे आतंकवाद और बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझते हुए राज्य ने नई दिशा पकड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सुधार, बैंकिंग क्षेत्र, नक्सलवाद, सीमाई चुनौतियां, जम्मू-कश्मीर, महामारी और वैश्विक युद्धों ने नेतृत्व की परीक्षा ली। लेकिन इन 25 वर्षों का एक सूत्र जो स्थायी रहा- संकट को रुकावट नहीं, बल्कि उससे जूझते हुए बदलाव का अवसर बना देना। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे आदर्शवादी नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, जिनका लक्ष्य देश और उसका गौरव स्थापित करना है। अपने 25 वर्ष की शासन यात्रा में वे एक दूरदर्शी नेता बन चुके हैं जो कभी टुकड़ों में नहीं सोचते बल्कि पूर्णता में सोचते हैं, दूर की सोचते हैं और जो सोचते हैं उसे पूरा करते हैं।

गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास का अलग मॉडल बनाने की दिशा में काम शुरू किया, जिसके लिए खासतौर से स्कूली शिक्षा पर फोकस किया। लेकिन इसी बीच गुजरात दंगे की वजह से विरोधियों को उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका मिल गया। लेकिन वे इन तीक्ष्ण हमलों से कमजोर नहीं पड़े, बल्कि मजबूती के साथ काम करते रहे। नतीजा होता था कि हर बार विरोधी पस्त पड़ जाते थे। लेकिन पीएम मोदी की ऐसी क्या खासियत है कि विरोधी उन्हें घेर नहीं पाते? अगर इसका जवाब जानना-समझना हो तो उसके लिए नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की बारीकियों को जानना होगा। उनके सोचने के तरीके को समझना होगा। दरअसल पीएम मोदी किसी भी काम की योजना के बारे में सोचते हैं तो उसकी शुरुआत नतीजों से होती है। यानी किस नीति, कथन और योजना का असर क्या होगा उसे जमीन पर क्रियान्वयन से सोचना शुरू करते हैं। उनके सोचने का अलग अंदाज ही उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करता है। उनकी इस सोच का नतीजा यह निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी योजना को तब बाहर लेकर आते हैं जब उसे जमीन पर उतारने की पूरी तैयारी हो जाती है।

यह कालखंड केवल 25 वर्ष की यात्रा भर नहीं हैं, बल्कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का ध्येय है। इस दौरान गरीबों के कल्याण, मध्यम वर्ग को मजबूत करने, महिलाओं को सशक्त बना नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास, किसान हितैषी नीतियों के जरिए बुवाई के हर चरण में अन्नदाताओं की चिंता का समाधान करना, युवाओं के लिए शिक्षा-रोजगार के अवसर, सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता के साथ राष्ट्र के विकास की अविस्मरणीय पहल है। यह 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य का आधारस्तंभ बन चुका है। कोई भी योजना हो उसके पीछे पीएम मोदी के संघर्ष भरे जीवन की एक कहानी है, उस दर्द को उन्होंने बेहद करीब से महसूस किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा को अगर चंद शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने विकासवाद को मुख्यधारा में लाकर अन्य सामाजिक कुरीतियों को धराशायी किया है और विकास देश की राजनीति, कार्यनीति और राष्ट्रनीति का मुख्य आधार बन गया है।

आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की शासन यात्रा के 25 वर्ष को उनकी विशिष्ट कार्यशैली, कार्यों और परिणामों से...

25 चुनौती, 25 साल एक राजनेता का सफर

25 वर्षों की यह यात्रा 25 चुनौतियों की सूची भर नहीं है। यह संकटों के बीच लिए गए फैसलों और उनसे बने बदलावों की कहानी है। इस यात्रा का सूत्र है- संकट को अंत नहीं, नए संकल्प की शुरुआत मानना। इसी सूत्र से 25 वर्ष में देश को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी...

1. संकट में गुजरात, नई शुरुआत का अवसर

अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य भूकंप, सूखे, सहकारी बैंक संकट से जूझ रहा था। पुनर्निर्माण को गति देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कच्छ भेजा गया। चेक डैम, नहर विस्तार व जल संरक्षण को प्राथमिकता मिली। 2003 में देश का पहला राज्य आपदा प्रबंधन कानून बना।

2. जब हिंसा के चक्र से मुक्त हुई पूरी पीढ़ी

फरवरी 2002 में गोधरा कांड और बाद की हिंसा ने स्थिति गंभीर कर दी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून-व्यवस्था, निवेश और रोजगार पर ध्यान देकर हिंसा का चक्र रोक दिया, 24 वर्षों में वैसी हिंसा दोबारा नहीं हुई।

3. पहली चुनावी परीक्षा, मिली अधिक मजबूती

2002 में नरेंद्र मोदी ने विधानसभा भंग कर 14 महीने के काम पर जनादेश मांगा। दिसंबर चुनाव में भाजपा को 182 में से 127 सीटें और 49.85 प्रतिशत वोट मिले।

4. आतंकवाद के खतरे के बीच स्थिरता

सितंबर 2002 में अक्षरधाम हमला और जुलाई 2008 में अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए। इन्हें सांप्रदायिक हिंसा में बदलने नहीं दिया गया, सुरक्षा मजबूत हुई और दिशा नहीं बदली।

5. पानी की कमी से जल सुरक्षा तक

नर्मदा बांध योजना 1961 से दशकों तक रुकी रही। 1.8 लाख से अधिक चेक डैम बने, सुजलाम सुफलाम व सौनी योजना से पानी पहुंचाया गया। 2017 में बांध पूरी ऊंचाई तक पहुंचा, जिससे 9,000 से अधिक गांवों, 170 शहरों को पेयजल मिला। गुजरात ने पानी का इंतजार करने के बजाय पानी के साथ विकास करना शुरू किया।

6. बाढ़ के बाद नई व्यवस्था

2006 में तापी बाढ़ से सूरत का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा डूबा, जिसके बाद जल निकासी व चेतावनी व्यवस्था मजबूत हुई। आठ साल बाद जम्मू-कश्मीर बाढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे और बाद में दिवाली मनाने फिर गए। प्रतिक्रिया का तरीका एक रहा-स्थिति को समझना, तेजी से काम करना और जमीन की जटिलताओं का समाधान करना।

7. आरोपों के बीच बदलाव का दशक

2002 के बाद नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे, पर उन्होंने बदले की जगह काम को जवाब बनाया। 2007 और 2012 में गुजरात ने उन्हें फिर चुना।

8. पटना धमाके

27 अक्टूबर 2013 को पटना रैली के आसपास सात बम धमाकों में छह मौतें और 85 घायल हुए। धमाके के बावजूद नरेंद्र मोदी ने भाषण जारी रखा, रैली पूरी की और भीड़ से शांत रहने की अपील की।

9. 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार

नरेंद्र मोदी ने नौ महीनों में करीब 400 रैलियां और तीन लाख किमी यात्रा की। 2014 में भाजपा को 282 सीटें मिलीं और 30 वर्षों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।

10. 'फ्रेजाइल फाइव' से तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था

2013 में भारत 'फ्रेजाइल फाइव' में था, महंगाई करीब 10% थी। महंगाई लक्ष्य, आईबीसी, जीएसटी सुधारों के बाद कई वैश्विक संकटों के बावजूद अर्थव्यवस्था बढ़ती रही; वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में दर 7.8% रही।

11. कारोबार करना आसान

2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 142वें स्थान पर था। जीएसटी, डिजिटल मंजूरियों, फ्रेट कॉरिडोर, आईबीसी जैसे कदमों से 2020 तक भारत 63वें स्थान पर पहुंचा।

12. बैंकिंग क्षेत्र की सफाई

'फोन बैंकिंग' और एवरग्रीनिंग ने बैंकों की असली स्थिति छिपाई थी। एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद खराब कर्ज करीब 15 प्रतिशत सामने आया। '4**R**' रिफॉर्म की रणनीति अपनाई गई। आईबीसी ने इसे मजबूती दी।

13. नक्सलवाद का अंत

2010 दंतेवाड़ा हमले में 76 जवान मारे गए थे; 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। सुरक्षा अभियानों के साथ सड़क-स्कूल-बैंकिंग सुविधाएं पहुंचीं। मुख्यधारा में लौटने वालों की संख्या 421 से बढ़कर सालाना 6,558 हुई। मार्च 2026 में कोई जिला नक्सल प्रभावित नहीं बचा।

14. संप्रभुता की रक्षा

2017 में डोकलाम में भारत-चीन सेनाएं 73 दिन आमने-सामने रहीं और भारत पीछे नहीं हटा। 2020 गलवान में भी सेना डटी रही। 'राष्ट्र प्रथम' आधार बना।

15. जीएसटी: एक देश, एक कर व्यवस्था

17 वर्षों की कोशिश जुलाई 2017 में जीएसटी से पूरी हुई। पुराने बकाये और राजस्व वृद्धि की गारंटी से सहमति बनी, देश एक साझा बाजार बना।

16. पूर्वोत्तर और कश्मीर तक पहुंच

सितंबर 2025 में आइजोल रेल से जुड़ा, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला लाइन 28 वर्षों बाद जून 2025 में शुरू हुई। चिनाब पुल ने कश्मीर कनेक्टिविटी को नया आधार दिया।

17. पूर्वोत्तर में शांति

2019 के बाद 12 समझौतों में स्वायत्तता, सहायता, पुनर्वास की व्यवस्था हुई। करीब 11 हजार उग्रवादियों ने हथियार छोड़े, घटनाओं में 71 प्रतिशत कमी आई और अप्रैल 2022 में बोडोलैंड से अफस्पा हटा।

18. आतंकवाद के खिलाफ नई नीति

2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट के बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एक रात में पाकिस्तान के नौ ठिकाने निशाना बने। नीति स्पष्ट हुई कि आतंकी हमले का सैन्य जवाब होगा। आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों को अलग-अलग नहीं माना जाएगा।

19. अनुच्छेद 370 : एक देश-एक संविधान

70 वर्षों से लागू अनुच्छेद 370, वर्ष 2019 में हटाया गया। राष्ट्रपति आदेश, संसद प्रस्ताव, पुनर्गठन कानून एक ही दिन पारित हुए। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया बरकरार रखी इस बदलाव के बाद 2024 में विधानसभा चुनाव हुए।

20. अयोध्या में श्रीराम मंदिर

पांच शताब्दी के इंतजार के बाद नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विवादित स्थल मंदिर निर्माण के लिए सौंपा गया। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, नवंबर 2025 में धर्म ध्वजारोहरण के साथ मुख्य निर्माण पूरा हुआ।

21. रेल पटरियों ने बढ़ाई भारत की रफ्तार

2008 में स्वीकृत फ्रेट कॉरिडोर पर 2014 तक एक किमी भी पटरी नहीं बिछी थी। इसके बाद निर्माण और निवेश में तेजी आई। बाद में 45,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च से मालगाड़ी परिवहन तेज हुआ, जबकि पहले सिर्फ 4,000 करोड़ खर्च हुए थे।

22. दो अरब वैक्सीन डोज

भारत बायोटेक-आईसीएमआर की कोवैक्सिन और पुणे में कोविशील्ड उत्पादन से जनवरी 2021 का अभियान दो अरब डोज तक पहुंचा। कोविन ने व्यवस्था संभाली और भारत ने करीब 100 देशों को वैक्सीन दी।

23. नदियों की ताकत

दिसंबर 2024 में केन-बेतवा परियोजना शुरू हुई। इससे बुंदेलखंड के 11 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का लक्ष्य है। जलमार्ग माल ढुलाई 2013-14 के 1.8 करोड़ टन से 2024-25 में 14.5 करोड़ टन हुई। अप्रैल 2025 पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि स्थगित की गई।

24. रूस-यूक्रेन युद्ध

फरवरी 2022 युद्ध के बाद ऑपरेशन गंगा में तीन सप्ताह में 22,500 भारतीय 90 उड़ानों से निकाले गए। रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर एक-तिहाई हुई, फिर भी महंगाई दोहरे अंक से नीचे रही।

25. पश्चिम एशिया का युद्ध

28 फरवरी 2026 के बाद होर्मुज बंद होने से ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ा, क्योंकि आधा कच्चा तेल इसी मार्ग से आता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेहरान-वॉशिंगटन दोनों से बात की। आयात शुल्क कटौती और आपूर्ति जारी रहने से अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत दर से बढ़ी।

"आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं। पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है, तो भारत की सेनाएं घर में घुसकर मारती हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक शांति बढ़ी है। माओवादी आतंक, नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

रिफॉर्म्स : भारत की शासन-व्यवस्था में सुधारों का युग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्ष की सुशासन यात्रा ने भारत में सुधारों के नए युग की स्थापना की है। इस अवधि में गुजरात से लेकर केंद्र तक शासन के कई क्षेत्रों में ऐसे संस्थागत बदलाव हुए, जिन्होंने योजनाओं, प्रक्रियाओं और काम करने के तरीके को बदला। पानी से लेकर बैंकिंग, कर व्यवस्था से लेकर श्रम, शिक्षा से लेकर अंतरिक्ष और कानून से लेकर सामाजिक सुधार तक, इन पहलों ने शासन के काम करने के तरीकों में बदलाव को केंद्र में रखा...

गुजरात में किए गए सुधार

1. जल सुधार, 2003

सूखे से जूझ रहे गुजरात में चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज कुएं और नहरों को एक योजना से जोड़ा गया। सुजलाम सुफलाम और सौनी से पानी और सिंचाई क्षमता बढ़ी। 2019 तक 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बने।

2. निर्मल गुजरात, 2006

स्वच्छता की जिम्मेदारी पंचायतों, स्कूलों, महिला समूहों और स्थानीय संस्थाओं तक पहुंचाई गई। यही तरीका आगे स्वच्छ भारत मिशन का आधार बना।

3. निवेशकों के लिए सिंगल विंडो प्रणाली- 2013

मंजूरियों को सिंगल विंडो से जोड़ने की शुरुआत हुई, जो बाद में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। आज यह 32 केंद्रीय मंत्रालयों को 33 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ती है।

4. गुजरात में पत्तन क्रांति

समुद्र तट को औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया गया। पत्तनों को सड़क, रेल, बिजली और उद्योगों से जोड़ा गया। मुंद्रा, हजीरा और पिपावाव इसके उदाहरण बने।

अदायगी, कृषि और मानव पूंजी

5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, 2014

जन धन, आधार और मोबाइल के जरिए लाभ सीधे सत्यापित बैंक खातों में पहुंचने लगे। 320 योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांसफर हुआ, जिससे 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत का अनुमान है।

6. नीम लेपित यूरिया, 2015

यूरिया पर नीम की परत से कालाबाजारी और औद्योगिक उपयोग पर रोक लगी। किसानों को यूरिया उपलब्धता बढ़ी और सरकारी खजाने को करीब 10,000 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

29 जुलाई 2020 को मंजूर नीति ने 1968 से लागू 10+2 संरचना की जगह 5+3+3+4 संरचना अपनाई। शुरुआती वर्ष की शिक्षा को व्यवस्था में शामिल किया गया। कला-विज्ञान-वाणिज्य-व्यावसायिक शिक्षा की कठोर सीमाएं कम हुईं।

8. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019

चिकित्सा शिक्षा के नियमन को बहु-परिषद व्यवस्था में बदला गया। मेडिकल कॉलेज 2014 के 387 से बढ़कर 846 से अधिक हुए। एमबीबीएस सीटें 51,348 से बढ़कर 1,39,864 से अधिक और स्नातकोत्तर सीटें 30,191 से बढ़कर करीब 86,360 हुईं।

अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण

9. बैंकिंग सुधार, 2014

परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा से बैंकों की वास्तविक स्थिति सामने आई। पूंजी बढ़ोतरी, विलय और दिवाला प्रक्रिया से बैंकिंग व्यवस्था मजबूत हुई।

10. उदार एफडीआई नीति, 2014

विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमाएं और प्रक्रियाएं आसान हुईं। 2014-25 में भारत ने 748.78 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया।

11. फेमा और वैश्विक वित्तीय एकीकरण

विदेशी मुद्रा, बाहरी उधार, विदेशी निवेश और सीमा-पार लेनदेन के नियम सरल किए गए, जिससे वैध कारोबार की रुकावटें कम हुईं। भारतीय कंपनियों के लिए विदेश में कारोबार करना आसान हुआ।

12. दिवाला व दिवालियापन संहिता- आईबीसी, 2016

डूबती कंपनियों के लिए समयबद्ध प्रक्रिया आई और लेनदारों की भूमिका केंद्रीय हुई। मार्च 2026 तक 1,419 मामलों में समाधान योजनाएं मंजूर हुईं और करीब 4.32 लाख करोड़ रुपये वापस मिले।

13 जीएसटी, 2017

कई केंद्रीय-राज्य करों की जगह साझा कर व्यवस्था आई। इससे भारत एकल बाजार बना और पंजीकृत करदाताओं व कर संग्रह में वृद्धि हुई।

14. आयकर सुधार, 2014

फेसलेस असेसमेंट से करदाता और अधिकारी का सीधा संपर्क कम हुआ। नई कर व्यवस्था और 2025 के नए आयकर कानून ने दर, धारा और प्रक्रिया को सरल बनाया। बजट 2025-26 में 12 लाख रु. तक की वार्षिक आय पर आयकर नहीं लगेगा और वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती मिलाकर यह सीमा 12.75 लाख रुपये।

15. MSME की संशोधित परिभाषा, 2020 व 2025

निवेश और कारोबार के संयुक्त पैमाने से छोटी कंपनियों के विकास की बाधा कम हुई। 2025 में सीमाएं और बढ़ाई गईं ताकि कंपनियां लाभ न खोएं।

16. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं (पीएलआई), 2020

मार्च 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपये निवेश और 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ। 15.2 लाख करोड़ रुपये का सामान निर्यात हुआ। साथ ही, करीब 14 लाख रोजगार सृजित हुए।

> *भारत की नीति-निर्णयों में आई ये गति दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

कानून, न्याय और जीवन-यापन में आसानी

17. वाणिज्यिक न्यायालय, 2015

व्यावसायिक विवादों के लिए अलग व्यवस्था, समय-सीमा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं शुरू हुईं। शहरों में विवाद निपटारे का समय वर्षों से घटकर महीनों में आ गया। न्याय विभाग के अनुसार, दिल्ली में फैसले का समय 424 दिन और मुंबई में 306 दिन रह गया।

18. पुराने कानूनों का अंत और जन विश्वास कानून, 2023

2014 से अब तक 1,500 से अधिक केंद्रीय कानून हटाए गए। 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर, छोटी तकनीकी गलतियों में सिविल जुर्माने का रास्ता अपनाया गया।

19. भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता ने 1860 की भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। यह औपनिवेशिक मानसिकता से आजादी का पर्याय बनी। महिलाओं-बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने की प्राथमिकता मिली। संगठित अपराध, आतंकवाद व भीड़ हिंसा यानी मॉब लिंचिंग के प्रावधान जुड़े।

20. श्रम संहिताएं, 2025

29 पुराने श्रम कानूनों की जगह वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़ी चार संहिताएं लागू हुईं। इससे अनुपालन सरल हुआ और गिग-प्लेटफॉर्म श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए।

रणनीतिक क्षमता

21. अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार, 2020

निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों का रास्ता खुला। इन-स्पेस के जरिए संस्थागत व्यवस्था बनी। 2026 तक करीब 440 पंजीकृत स्टार्टअप सामने आए और निजी निवेश 618 मिलियन डॉलर से अधिक हुआ। 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट के विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और पहले ही प्रयास में कक्षा में पहुंच गया।

22. रक्षा सुधार, 2020

रक्षा उत्पादन में भारतीय डिजाइन-निर्माण को प्राथमिकता मिली। रक्षा निर्यात 2013-14 के करीब 680 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,400 करोड़ रुपये से अधिक हुआ। हथियार खरीदने वाला देश अब निर्यातक बन गया है।

23. सेमीकंडक्टर मिशन, 2021

भारत में चिप फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और डिजाइन की पूरी श्रृंखला विकसित करने की योजना बनी। करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये की दस परियोजनाओं को मंजूरी मिली। यह गुजरात, असम और अन्य राज्यों में फैले हैं ताकि एक से ज्यादा इलाकों में यह क्षमता विकसित की जा सके।

सामाजिक सुधार

24. तीन तलाक, 2019

तुरंत तीन तलाक को अमान्य और दंडनीय बनाया गया। साथ ही, गुजारा-भत्ता और नाबालिग बच्चों के संरक्षण का प्रावधान किया गया। कानून लागू होने के एक साल में ऐसे मामलों की रिपोर्ट में 82 प्रतिशत कमी आई। संवैधानिक सुरक्षा उन महिलाओं तक पहुंची, जिन्हें कानून ने लंबे समय से नजरअंदाज कर रखा था।

25. वक्फ सुधार, 2025

वक्फ संपत्तियों से जुड़े दावों में जांच-अपील व्यवस्था मजबूत की गई। सरकारी जमीन पर दावों की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराने और उच्च न्यायालय में अपील का रास्ता खुला। अब वक्फ के दावे भी सबूत पर आधारित होंगे।

नए भारत की भव्य निर्माण गाथा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष की यात्रा को 'भारत का आर्किटेक्चरल मार्वल्स' माना जाता है। इन वर्षों में देश में हुए अनेक भव्य निर्माण ने भारत की बदलती विकास यात्रा की गौरवमयी तस्वीर पेश की है। पुलों और सुरंगों से लेकर हवाई अड्डों, बंदरगाहों, शहरी परिवहन, संसद, स्मारकों, संग्रहालयों, तीर्थस्थलों और स्मार्ट शहरों तक फैली इन परियोजनाओं ने कनेक्टिविटी, सुविधा, विरासत और भविष्य की जरूरतों को एक साथ साधने का प्रयास किया है। यही विविधता इन निर्माणों को 'न्यू इंडिया' के भव्य वास्तु और विकास मानचित्र की महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में दर्शाती है।

1. **बोगीबील और डॉ. भूपेन हजारिका सेतु-पूर्वोत्तर की सामरिक कनेक्टिविटी:** ब्रह्मपुत्र पर 4.94 किमी लंबा बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा संयुक्त रेल-सड़क पुल है। 25 दिसंबर 2018 को उद्घाटित इस पुल ने डिब्रूगढ़-ईटानगर की सड़क दूरी 150 किमी और रेल दूरी लगभग 200 किमी घटाई। वहीं 9.15 किमी लंबे डॉ. भूपेन हजारिका सेतु ने ऊपरी असम को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से स्थायी सड़क संपर्क दिया। भूपेन हजारिका सेतु से लगभग 165 किमी की अंतरराज्जीय दूरी कम हुई। दोनों पुल सैन्य आवागमन के अनुरूप बनाए गए हैं।

2. **अटल सेतु और सुदर्शन सेतु-समुद्री संपर्क के नए आयाम:** मुंबई का 21.8 किमी लंबा छह लेन वाला अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल और समुद्री पुल है। इससे सेवरी-न्हावा शेवा यात्रा करीब दो घंटे से घटकर 20 मिनट की हुई। गुजरात का 2.32 किमी लंबा सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल-स्टेड पुल है, जिसने बेट द्वारका को स्थायी सड़क संपर्क दिया। इसके पैदल पथों पर भगवद्गीता के श्लोक और डेक पर लगभग 1 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल हैं।

3. **चिनाब और अंजी खड्ड-कश्मीर रेल संपर्क की कड़ी**
नदी तल से 359 मीटर ऊंचा और 1,315 मीटर लंबा चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। 6 जून 2025 को उद्घाटन के साथ कश्मीर रेल लाइन के दुर्गम हिस्से का संपर्क पूरा हुआ। इसी दिन अंजी खड्ड पुल भी शुरू हुआ, जो भारत का पहला केबल-स्टेड रेलवे पुल है। 725 मीटर लंबे इस पुल का **Y**-आकार का पाइलन 193 मीटर ऊंचा है।

4. **नया पंबन पुल-समुद्र के ऊपर आधुनिक रेल संपर्क**
भारत के पहले वर्टिकल-लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल ने रामेश्वरम के लिए रेल संपर्क बहाल किया। 550 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल का 72.5 मीटर का नेविगेशनल स्पैन 17 मीटर तक उठ सकता है। विशेष कोटिंग वाले स्टेनलेस स्टील रिइनफोर्समेंट से इसे समुद्री वातावरण से दीर्घकालिक सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई है।

5. **अटल सुरंग और सेला सुरंग: सीमावर्ती क्षेत्रों को वर्षभर संपर्क** : 9.02 किमी लंबी अटल सुरंग ने लाहौल-स्पीति को वर्ष भर संपर्क दिया और मनाली-सरचू दूरी 46 किमी घटाई। सेला सुरंग ने भारी बर्फबारी से प्रभावित मार्ग पर तवांग के लिए वर्षभर संपर्क उपलब्ध कराया। इसकी सुरंग 1,555 मीटर लंबी है। 8.6 किमी संपर्क एवं एप्रोच सड़कें भी विकसित की गई हैं।

6. **केम्पेगौड़ा और गुवाहाटी हवाई अड्डे- बढ़ती विमानन क्षमता:** बेंगलुरु के टर्मिनल-2 ने हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5-6 करोड़ की। ग्रीन वॉल, हैंगिंग गार्डन और आउटडोर गार्डन इसकी विशेषताएं हैं। वहीं गुवाहाटी के नए टर्मिनल ने क्षमता 34 लाख से बढ़ाकर 1.3 करोड़ से अधिक की। इसमें लगभग 140 मीट्रिक टन बांस और करीब एक लाख देशज पौधों वाला 'स्काई फॉरेस्ट' है।

7. **जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा- एनसीआर का दूसरा प्रमुख एविएशन गेटवे:** 11,200 करोड़ रुपये की लागत वाले पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को हुआ। इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवाई संपर्क आवश्यकताओं को पूरा करना है। पूरी तरह विकसित होने पर इसे भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल करने की योजना है।

8. **विझिंजम बंदरगाह-भारत का समुद्री ट्रांसशिपमेंट केंद्र:** 2 मई 2025 को उद्घाटित विझिंजम भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट और पहला सेमी-ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। लगभग 20 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट के कारण बड़े मालवाहक जहाज यहां आ सकते हैं। इसका उद्देश्य विदेशी बंदरगाहों पर होने वाले ट्रांसशिपमेंट को भारत लाना और उससे होने वाला राजस्व देश में बनाए रखना है।

9. **कोच्चि वाटर मेट्रो और नमो भारत:** शहरी परिवहन के नए मॉडल: कोच्चि वाटर मेट्रो भारत की पहली वाटर मेट्रो है। 78 बैटरी-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं 15 मार्गों पर 38 टर्मिनलों को जोड़ती हैं। यह बेड़ा इस स्तर के पैमाने पर बैटरी ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला वाटर-मेट्रो नेटवर्क है। दूसरी ओर 82.15 किमी लंबा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति के लिए डिजाइन किया गया है।

10. **नमो घाट और वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल नदी आधारित संपर्क :** 95 करोड़ रुपये की लागत से विकसित नमो घाट में व्यूइंग डेक, कैफेटेरिया, हेरिटेज म्यूरल और क्रूज बर्थ विकसित किए गए। वाराणसी मल्टी-मॉडल टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर अपनी तरह का पहला टर्मिनल है, जहां 1,500-2,000 टन क्षमता वाले जहाज चल सकते हैं। यहीं से स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग कंटेनर सेवा शुरू हुई।

11. **स्वर्णिम संकुल और नया संसद भवन- सुशासन का नया परिसर:** गांधीनगर का स्वर्णिम संकुल विभिन्न राज्य विभागों को एक परिसर में लाने की पहल थी, जिससे साझा सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा हुई। नई दिल्ली में नए संसद भवन का त्रिकोणीय परिसर लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 सीटों से सुसज्जित है। 28 मई 2023 को उद्घाटित भवन में देश के विभिन्न राज्यों की सामग्री और 'सेंगोल' को स्थापित किया गया है।

12. **सेंट्रल विस्टा-कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ:** 19 महीने में पुनर्विकसित कर्तव्य पथ का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को हुआ। कर्तव्य भवन-3 और सेवा तीर्थ के शुरू होने के साथ विभिन्न किराए के भवनों में चल रहे मंत्रालयों को साझा सचिवालय परिसर में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कर्तव्य भवन-3 को सामान्य भवनों की तुलना में 30 प्रतिशत कम ऊर्जा खपत के लिए डिजाइन किया गया है।

13. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-राष्ट्रभावना का विराट प्रतीक
182 मीटर ऊंची यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटित प्रतिमा की ऊंचाई गुजरात विधानसभा की 182 सीटों को दर्शाती है। देशभर के किसानों ने पुराने कृषि उपकरणों से प्राप्त लोहा भेजकर इसमें जनभागीदारी की।

14. राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बलिदान को नमन : राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की स्मृति में भारत का पहला राष्ट्रीय स्मारक है। इसमें 25,942 सैनिकों के नाम अंकित हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को समर्पित पहला राष्ट्रीय स्मारक है। इसकी 'वॉल ऑफ वेलोर' पर शहीद पुलिसकर्मियों के नाम अंकित हैं।

15. स्मृतिवन और जलियांवाला बाग- त्रासदी की स्मृति और इतिहास: भुज में 470 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित स्मृतिवन में 13,000 से अधिक पीड़ितों के नाम, तीन लाख से अधिक पेड़ों वाला मियावाकी वन और 5डी सिस्मिक सिम्युलेटर है। जलियांवाला बाग के पुनर्विकसित परिसर में जनरल डायर के सैनिकों के प्रवेश मार्ग को मूर्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा नई गैलरी और साउंड-एंड-लाइट शो जोड़े गए हैं।

16. नालंदा विश्वविद्यालय- ज्ञान की परंपरा का आधुनिक विस्तार: 455 एकड़ में फैले नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को हुआ। सौर ऊर्जा से संचालित नेट-जीरो परिसर में 2,000 लोगों का एम्फीथिएटर और 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कमल सागर है। वर्षा जल संचयन के लिए बिहार की पारंपरिक 'आहर-पाइन' प्रणाली का उपयोग किया गया है।

17. प्रधानमंत्री संग्रहालय और दांडी कुटीर-आधुनिक प्रस्तुति में इतिहास: प्रधानमंत्री संग्रहालय 14 अप्रैल 2022 को खुला। यह प्रत्येक भारतीय प्रधानमंत्री को समर्पित पहला संग्रहालय है। होलोग्राम और इंटरैक्टिव कक्षों के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा प्रस्तुत की गई है। दांडी कुटीर में 41 मीटर ऊंचे शंक्वाकार गुंबद के भीतर 3डी मैपिंग, होलोग्राफी और 360-डिग्री प्रोजेक्शन के जरिए महात्मा गांधी का जीवन प्रस्तुत किया गया है।

18. जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर: जनजातीय समुदायों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को समर्पित राष्ट्रीय संग्रहालय कार्यक्रम के प्रस्तावित 11 संग्रहालयों में से 2026 तक चार का उद्घाटन हो चुका है। पहला रांची की पुरानी सेंट्रल जेल में है। लोथल में विकसित किया जा रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों के समुद्री इतिहास को समर्पित है।

19. महात्मा मंदिर, भारत मंडपम और यशोभूमि-सम्मेलन क्षमता का विस्तार: गांधीनगर का महात्मा मंदिर लगभग 40 एकड़ में फैला है। इसके मुख्य सभागार में 6,000 लोगों की क्षमता है। भारत मंडपम में 7,000 लोगों के सभागार और 3,000 क्षमता का एम्फीथिएटर है। यशोभूमि में 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक प्रदर्शनी क्षेत्र और 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाले सम्मेलन कक्ष हैं।

20. रुद्राक्ष और नरेंद्र मोदी स्टेडियम-संस्कृति से खेल तक: वाराणसी का रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग व सम्मेलन केंद्र शिवलिंग के आकार में बना है और 108 एल्युमिनियम रुद्राक्ष आकृतियों से सुसज्जित है। लगभग 1,200 लोगों की क्षमता वाला यह केंद्र भारत-जापान स्थापत्य एवं तकनीकी साझेदारी का उदाहरण है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम लगभग 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।

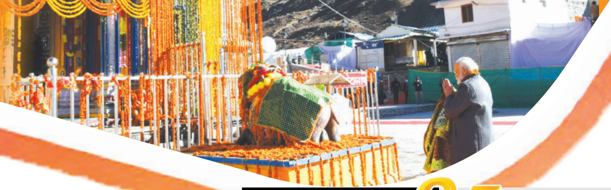

21. साबरमती रिवरफ्रंट और कांकरिया झील-शहरी सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्पः साबरमती रिवरफ्रंट में लगभग 205 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनर्विकास कर 11.25 किमी सार्वजनिक नदी तट बनाया गया। इसका 300 मीटर लंबा पतंग-प्रेरित अटल पैदल यात्री पुल विशेष आकर्षण है। 15वीं शताब्दी की कांकरिया झील का पुनर्विकास कर 2.3 किमी लेकफ्रंट बनाया गया और यहां मनोरंजन की कई सुविधाएं विकसित की गईं।

22. काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक- तीर्थयात्रा को नया स्वरूपः काशी विश्वनाथ धाम के 23 भवनों ने ललिता घाट को मंदिर से जोड़ा और गंगा से मंदिर तक यात्रा सुगम बनाई। उज्जैन का लगभग 900 मीटर लंबा महाकाल लोक 108 बलुआ पत्थर के स्तंभों से सुसज्जित है, जिन पर भगवान शिव के आनंद तांडव की मुद्राएं उकेरी गई हैं।

23. केदारनाथ, सोमनाथ और अंबाजी-विरासत भी, विकास भी मंत्रः केदारनाथ में 2013 की बाढ़ के बाद आपदा-रोधी पुनर्विकास किया गया, जहां 35 टन वजनी आदि शंकराचार्य प्रतिमा स्थापित की गई। सोमनाथ में 1.48 किमी का 'समुद्र दर्शन पथ', विशेष दीर्घा और पुराने क्षेत्र का पुनर्विकास हुआ। अंबाजी में 1,632 करोड़ रुपये की शक्ति कॉरिडोर परियोजना के तहत मंदिर, गब्बर पर्वत और मानसरोवर को जोड़ने तथा पार्किंग, अंडरपास और यात्री भवन जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

24. त्रिपुरा सुंदरी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर-परंपरा और पुनर्जागरण : मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास 51 शक्तिपीठ पार्क में शक्तिपीठों की प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर की मुख्य संरचना में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें पारंपरिक शिल्प तथा उत्कृष्ट पत्थरों का उपयोग हुआ है।

25. गिफ्ट सिटी, धोलेरा और चरंका-भविष्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जाः गिफ्ट सिटी भारत की पहली कार्यशील आईएफएससी और पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन और यूटिलिटी टनल को मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया। धोलेरा में भूखंड आवंटन से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। 2024 में स्वीकृत सेमीकंडक्टर संयंत्र यहां की पहली बड़ी फैक्टरी है। चरंका सोलर पार्क ने साझा भूमि, सड़क और बिजली इवेक्यूएशन सुविधाओं के जरिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन का साझा पार्क मॉडल सामने रखा।

25 पहल जनसेवा से जनभागीदारी तक

गुजरात से शुरू हुई विकास और सुशासन की यात्रा में अनेक ऐसी पहल हुई है, जिसने सेवा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है, अवसर बढ़े हैं और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। इस 25 वर्षों की यात्रा का सार है, सुशासन से सेवा, सेवा से सशक्तीकरण और सशक्तीकरण से विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। इन 25 वर्षों की यात्रा की 25 प्रमुख पहल...

1. कन्या शिक्षा और शाला प्रवेशोत्सव

जीईआर में सुधार । ड्रॉपआउट दर में कमी

- 2003 में शुरू हुई इन पहलों ने स्कूल नामांकन को प्रशासनिक लक्ष्य से सामाजिक उत्सव बनाया। मंत्रियों, अधिकारियों, शिक्षकों और समुदायों ने गांव-गांव जाकर बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया।

2. स्वागत

लाखों शिकायतें । 99% समाधान

- 2003 में शुरू 'स्वागत' प्लेटफॉर्म ने नागरिकों की शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और उनके समाधान की पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था बनाई। लाखों शिकायतों के 99% समाधान ने तकनीक को नागरिक और शासन के बीच प्रभावी सेतु बनाया।

3. ज्योतिग्राम योजना

18,000+ गांव । फीडर पृथक्करण के साथ 24×7 बिजली

- 2006 में फीडर पृथक्करण के माध्यम से कृषि और घरेलू बिजली आपूर्ति को अलग किया गया। 18,000 से अधिक गांवों में 24 घंटे विश्वसनीय थ्री-फेज बिजली पहुंची। कृषि बिजली सब्सिडी लगभग आधी हुई।

4. गरीब कल्याण मेला

अब तक 36,800 + करोड़ रुपये।
1.66 करोड़ लाभार्थी । 1600 मेले

2009 में शुरू इस पहल ने कल्याणकारी योजनाओं को फाइलों और बिचौलियों से निकालकर सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया। अब तक 1.66 करोड़ लाभार्थियों तक 36,800 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ पहुंचे और 1,600 से अधिक मेले आयोजित हुए।

5. वनबंधु कल्याण योजना

10-सूत्रीय विकास मिशन

2007 की इस 10 सूत्रीय पहल ने जनजातीय विकास को मिशन मोड में आगे बढ़ाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका, कौशल, सिंचाई, बुनियादी ढांचा और विद्युतीकरण को साथ लाकर जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर।

> *मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी-जान लगा देता हूं।*
>
> *-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

6. सागरखेड़ू सर्वांगी विकास योजना

60 लाख लोग । 3,000 तटीय गांव

- 2007 में शुरू योजना ने 3,000 तटीय गांवों और 60 लाख से अधिक लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका, सिंचाई, लवणता नियंत्रण, मत्स्यपालन और तटीय सुरक्षा को एक साथ जोड़ा। मछुआरों को जीपीएस, सुरक्षा उपकरण, सोलर लाइट और संकट-चेतावनी जैसी सुविधाएं भी मिलीं।

7. जन धन और डीबीटी

59+ करोड़ खाते । 3.17 लाख करोड़ रु. से अधिक जमा

- 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया। सितंबर, 2026 तक 59 करोड़ से अधिक खाते और 3.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा हुए। डीबीटी ने धन को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया। 53.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित हुए और 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत हुई।

8. मेक इन इंडिया

20 लाख करोड़+ रुपये का उत्पादन । पीएलआई से 14 लाख+ नौकरियां

- पीएलआई, सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रयासों से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपये हुआ। पीएलआई के 14 क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुईं।

9. स्वच्छ भारत मिशन

12+ करोड़ शौचालय

- 2014 में शुरू मिशन ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बने और 2019 तक गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण ने शहरों और कस्बों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नागरिक भागीदारी को बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वयं झाड़ू उठा आगे बढ़कर नेतृत्व किया था।

10. सामाजिक सुरक्षा

94 करोड़ लोग । सामाजिक सुरक्षा कवरेज: 64.3%

- पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और ई-श्रम जैसी पहलों ने औपचारिक रोजगार से बाहर रहने वालों तक सुरक्षा पहुंचाई। 2025 तक 94.3 करोड़ भारतीय सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए, जिससे कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 64.3% हुआ।
- नवंबर 2023 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) यह सुनिश्चित करने का एक केंद्रित मिशन है कि भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (**PVTGs**) विकास के हाशिए पर न रहें। 24,000+ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

11. सागरमाला कार्यक्रम

845+ परियोजनाएं । 6+ लाख करोड़ रुपये का निवेश

- 2015 में शुरू सागरमाला ने बंदरगाहों को सड़क, रेल, उद्योग और तटीय समुदायों से जोड़ने का प्रयास किया। 6.06 लाख करोड़ रुपये की 845 से अधिक परियोजनाएं चिन्हित हुईं, 315 पूरी हो चुकी। प्रमुख बंदरगाहों पर जहाजों का औसत टर्नअराउंड समय 2014 के 96 घंटे से घटकर 2025 में लगभग 49 घंटे हुआ। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 2014 के 873 एमटीपीए से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 1,728 एमटीपीए हो गई है।

12. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

57+ करोड़ लोन I 40 लाख+ करोड़ रुपये वितरित

- 2015 में शुरू पीएम मुद्रा योजना ने छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराया। 57 करोड़ से अधिक लोन में 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित हुए। 68% लोन महिलाओं और 51% एससी/एसटी/ओबीसी उधारकर्ताओं को मिले। 2024 में लोन की सीमा 20 लाख रुपये की गई।

13. स्टार्टअप इंडिया

2.5 लाख+ स्टार्टअप I 23.36 लाख+ नौकरियां

- 2016 में शुरू पहल ने उद्यमिता को राष्ट्रीय आकांक्षा बनाया। सितंबर 2026 तक 2.5 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 23 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कीं। लगभग आधे स्टार्टअप टियर-II और टियर-III शहरों से आते हैं और लगभग 50% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार है।

14. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: धुएं से मुक्ति

लगभग 11 करोड़+ कनेक्शन

- 2016 में शुरू उज्ज्वला ने मई 2026 तक 10.6 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए। इससे धुएं वाले ईंधन पर निर्भरता कम हुई और महिलाओं के स्वास्थ्य, समय तथा अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

15. डिजिटल भुगतान क्रांति- यूपीआई

24,162 करोड़ लेनदेन I 55+ करोड़ उपयोगकर्ता

- 2016 में शुरू यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को रोजमर्रा की सुविधा बनाया। 2016 के 1.78 करोड़ वार्षिक लेनदेन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ लेनदेन हुए। जून 2026 तक 55.5 करोड़ उपयोगकर्ता और जुलाई 2026 तक 741 बैंक इससे जुड़े थे। लेनदेन मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपये हो गया। यूपीआई अब 11 देशों में चालू है।

16. वस्तु एवं सेवा कर- जीएसटी

एक राष्ट्र- एक कर I वित्त वर्ष 2025 में 22 लाख करोड़+ रुपये सकल जीएसटी

- 2017 में लागू जीएसटी ने कई केंद्रीय और राज्य करों को साझा ढांचे में लाकर 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' की दिशा मजबूत की। करदाताओं की संख्या 2017 के 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 में 1.65 करोड़ हुई और वित्त वर्ष 2025-26 में सकल जीएसटी संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपये रहा।

17. आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सुरक्षा

5 लाख रुपये का कवर I 12 करोड़+ परिवार कवर

- जून 2026 तक, 37,413 सरकारी और निजी अस्पतालों में 12.69 करोड़ मरीजों का इलाज हुआ, जिससे आम जनता के 1.92 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तक भी इसका विस्तार हुआ।

18. जल जीवन मिशन

12 करोड़+ नल कनेक्शन I कवरेज 82% से अधिक

- 2019 में शुरू मिशन ने ग्रामीण घरों में नल के पानी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा। 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों से बढ़कर जून 2026 तक लगभग 16 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन मिला। 5 लाख से अधिक पानी समितियों और 24.8 लाख महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया।

19. पीएम-किसान

4 लाख करोड़+रुपये I 9.44 करोड़ किसान

- 2019 से किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिल रहे हैं। जुलाई 2026 तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचाए जा चुके हैं।

20. लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी

3 करोड़+ लखपति दीदी ।
स्वयं सहायता समूहों में 10.57 करोड़ महिलाएं

- लखपति दीदी ने ग्रामीण महिलाओं को सहायता से आगे बढ़ाकर स्थायी आय और उद्यमिता से जोड़ा। मई 2026 तक 3.07 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी थीं और 10.57 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में संगठित थीं। नमो ड्रोन दीदी के तहत 15,000 ड्रोन का लक्ष्य है।

21. भारत की सौर क्रांति

164 GW+ सौर ऊर्जा ।
14.8 GW रूफटॉप सोलर संयंत्र

- गुजरात की सौर पहल से शुरू अनुभव राष्ट्रीय विस्तार का आधार बना। भारत की स्थापित सौर क्षमता 2014 के 2.8 **GW** से बढ़कर जुलाई 2026 में लगभग 165 **GW** हुई। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अगस्त 2026 तक 51 लाख घर कवर हुए और 14.8 **GW** रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित हुई।

22. पीएम स्वनिधि

78 लाख+ स्ट्रीट वेंडर । 18,000+ करोड़ रु. लोन

- 2020 में शुरू योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को बिना जमानत कार्यशील पूंजी ऋण के लिए औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा। अगस्त 2026 तक 78 लाख से अधिक वेंडरों को 1.18 करोड़ से अधिक ऋण मिले।

23. पीएम गति शक्ति

16 मंत्रालय । इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एकीकृत मानचित्र

- 2021 में शुरू राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने 16 मंत्रालयों और विभागों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा को एकीकृत किया। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को एक साथ देखने से परियोजनाओं के बेहतर समन्वय और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने की दिशा मजबूत हुई। यह प्लेटफॉर्म अब 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा तैयार करता है।

24. स्वामित्व और प्राकृतिक खेती

3.30 लाख गांव सर्वेक्षित । 3.24 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड

- स्वामित्व योजना ने ड्रोन और **GIS** से ग्रामीण संपत्तियों का सटीक मानचित्रण कर संपत्ति अधिकारों को मजबूत किया। अगस्त 2026 तक 3.30 लाख गांवों में सर्वेक्षण और 3.24 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हुए। प्राकृतिक खेती के तहत 20 लाख से अधिक किसानों और 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जोड़ा गया।

25. खेलता राष्ट्र, जीतता राष्ट्र

1,000+ खेलो इंडिया केंद्र । 2,700+ एथलीट

- 1,000+ खेलो इंडिया केंद्र हैं। 2,700+ एथलीटों को सहायता मिल रही है। टोक्यो 2020 के सात ओलंपिक पदक, एशियाई खेलों में 107 पदक और 2022 की ऐतिहासिक थॉमस कप जीत इस बढ़ते खेल आत्मविश्वास की तस्वीर है। बीते 13 वर्षों में, भारत ने तीनों प्रमुख खेल मंचों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है: टोक्यो 2020 ओलंपिक में 7 पदक, हांग्झोऊ 2023 एशियाई खेलों में 107 पदक और गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 66 पदक।

25 अभूतपूर्व पहल जो बन गए जन-आंदोलन

शासन प्रमुख के रूप में पीएम मोदी 25 वर्ष की यात्रा ने भारत में एक नया आयाम स्थापित कर दिया है जिससे देश का हर नागरिक सरकार के साथ सीधा जुड़ाव महसूस कर रहा है। इस यात्रा में कई ऐसी पहल सामने आईं, जिन्होंने शासन, विकास, जनभागीदारी और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका के नए मानक स्थापित किए। इस यात्रा में विचारों को योजनाओं और योजनाओं को जनभागीदारी से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। यही वे पहल हैं, जिन्होंने घरेलू और वैश्विक स्तर पर नए मानक स्थापित करने की दिशा में भारत की विकास यात्रा को एक अलग पहचान दी।

1. वाइब्रेंट गुजरात

2003 में निवेश के लिए दुनिया को गांधीनगर आमंत्रित करने की पहल ने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की नई सोच रखी। सिंगल विंडो मंजूरी और नीतिगत प्रतिबद्धताओं के साथ निवेश आकर्षित करने का यह मॉडल बाद में अन्य राज्यों तक पहुंचा।

2. रण उत्सव

वर्ष 2005 में शुरू हुआ कच्छ का 'रण उत्सव' स्थानीय संगीत, कला, हस्तशिल्प और खानपान को पर्यटन से जोड़ने का माध्यम बना। सुदूर नमक का रेगिस्तान ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन का मॉडल बना और कारीगरों को नया बाजार मिला जो एक वैश्विक मॉडल बन गया।

3. कृषि महोत्सव

वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों को सीधे जोड़ते हुए कृषि सलाह को खेत की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्डों और निरंतर संवाद ने कृषि को मौसमी अभियान के बजाय सतत ज्ञान आंदोलन का रूप दिया।

4. वांचे गुजरात

'पूरा राज्य एक घंटा पढ़े' के आह्वान ने पढ़ने को व्यक्तिगत आदत से साझा सार्वजनिक संस्कृति में बदला। विद्यार्थियों और नागरिकों की जनभागीदारी के साथ पुस्तकालयों को भी बेहतर बनाया गया।

5. जन भागीदारी

नागरिकों को योजनाओं के निष्क्रिय लाभार्थी के बजाय शासन में भागीदार बनाने की सोच ने नीति निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी में उनकी राय और प्रतिक्रिया को स्थान दिया। इससे विकास में सक्रिय भागीदारी की भावना मजबूत हुई।

6. मन की बात

मासिक रेडियो संवाद ने प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच संचार का एक अलग माध्यम बनाया। नीतियों, अच्छे कार्यों और सामाजिक अभियानों की सरल चर्चा ने आधिकारिक संवाद को संबोधन से आगे बढ़ाया।

7. गुलामी की मानसिकता से मुक्ति

सड़कों, शहरों, इमारतों और संस्थानों से औपनिवेशिक नामों और प्रतीकों को हटाकर स्वदेशी पहचान को स्थान देने का प्रयास सार्वजनिक स्मृति और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की पुनर्प्राप्ति का माध्यम बना। अब 2035 तक पूरी तरह से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का लक्ष्य निर्धारित।

8. स्वयं छोड़ो अभियान (गिव इट अप)

एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की स्वैच्छिक अपील ने साझा जिम्मेदारी की भावना को सामने रखा। 1.13 करोड़ से अधिक परिवारों द्वारा सब्सिडी छोड़ने से मिली बचत का उपयोग उज्ज्वला योजना में कनेक्शन देने के लिए किया गया।

9. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

योग को वैश्विक मंच पर लाने के प्रयासों से 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की मान्यता मिली। इसके साथ ही यह भारतीय परंपरा वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की साझा पहल बनकर 190 से अधिक देशों में मनाई जाने लगी। इस बार भारत के बाहर ही 1,300 से अधिक स्थानों पर इसका आयोजन हुआ, जिनमें से कई ने गिनीज रिकॉर्ड भी बनाए।

10. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

पहले 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियां थीं। 2015 में शुरू की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना बालिका के जीवन, शिक्षा और अधिकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रवर्तन के संयुक्त अभियान से जोड़ा गया। बालिका की जीवन रक्षा और शिक्षा, राष्ट्रीय मिशन बन गई।

11. जनता के पद्म पुरस्कार

पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को व्यापक बनाकर ग्रामीण, दूरस्थ और जमीनी स्तर के योगदानकर्ताओं को राष्ट्रीय सम्मान के केंद्र में लाया गया। राष्ट्रीय पहचान अभिजात वर्ग से हटकर जन-उत्कृष्टता की ओर बढ़ी। गुमनाम नायकों की पहचान कर उन्हें सम्मानित किए जाने की नई परंपरा का उदय हुआ।

12. एक भारत, श्रेष्ठ भारत

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच भाषा, शिक्षा, संस्कृति, खानपान और त्योहारों के आदान-प्रदान ने एकता को संवैधानिक सिद्धांत से जीवंत अनुभव में बदलने का प्रयास किया।

13. यूपीआईः क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक पहल

डिजिटल भुगतान को उत्पाद के बजाय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित करने की सोच ने भुगतान को तत्काल, निःशुल्क और व्यापक बनाया। यूपीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को बदल दिया।

14. खेल महाकुंभ से खेलो इंडिया

गांव और विद्यालय स्तर तक प्रतियोगिताओं का विस्तार कर प्रतिभा पहचान को बड़े शहरों और चुनिंदा अकादमियों से बाहर लाया गया। खेल को युवा विकास का व्यापक माध्यम बनाया गया।

15. एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी)

हर जिले के विशिष्ट उत्पाद को ब्रांडिंग, जीआई टैग, ई-कॉमर्स और निर्यात सहायता से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी गई। कारीगरों और किसानों के लिए बाजार का दायरा बढ़ा।

16. आकांक्षी जिले और वाइब्रेंट विलेज

वास्तविक समय के डेटा, रैंकिंग और योजनाओं से पिछड़े क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी विकास की सोच लाई गई। सबसे कठिन क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया गया।

17. परीक्षा पे चर्चा

संवाद की नई परंपरा स्थापित हुई। परीक्षा के दबाव को सार्वजनिक संवाद का विषय बनाकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया। परीक्षा को तनाव के बजाय अवसर के रूप में देखने और समग्र विकास पर ध्यान देने की दिशा बनी।

> *"देश में कई सारी आपदाएं आईं, इतने बड़े-बड़े साइक्लोन हमने झेलें हैं लेकिन देश ने बहुत मजबूती से उनका सामना किया।"*
>
> *-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

18. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को पर्यटन, मनोरंजन और सम्मेलनों से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। इस स्मारक ने स्थानीय क्षेत्र में निरंतर रोजगार और पर्यटन का आधार तैयार किया है, जिसके परिणामस्वरूप पहले सात वर्षों में ही पर्यटकों की संख्या 2.75 करोड़ से अधिक हो गई।

19. वंदे भारत ट्रेनें

स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की क्षमता के साथ आधुनिक रेल यात्रा को नया रूप दिया गया। इसने भारत की जटिल रेल प्रणालियों में आत्मनिर्भर क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वदेशी, सहजता, सुगमता का प्रतीक बनी।

20. आत्मनिर्भर भारत

रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में समयबद्ध क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन ने आत्मनिर्भरता को प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ा। आत्मनिर्भरता का आह्वान जन आंदोलन बन गया।

21. स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन

'वोकल फॉर लोकल' ने उपभोक्ताओं से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इससे कारीगरों, हथकरघा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मांग और बाजार से जोड़ने की सोच सामने आई।

22. मिशन लाइफ: पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली

जलवायु परिवर्तन के समाधान को सरकारों और उद्योगों से आगे बढ़ाकर व्यक्ति की जीवनशैली से जोड़ा गया। सचेत और संयमित उपभोग को साझा जिम्मेदारी के रूप में सामने रखा गया।

23. श्री अन्न (मोटा अनाज)

बाजरा, ज्वार और रागी जैसी पारंपरिक फसलों को उत्पादन सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूली भोजन और निर्यात प्रोत्साहन से जोड़कर पोषण व जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया गया। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' घोषित किया, जिससे वर्षा आधारित खेती करने वाले किसानों को एक लाभदायक फसल मिली।

24. नारी शक्ति वंदन अधिनियम

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत आधार देता है। पंचायत से संसद तक महिला-नेतृत्व वाले विकास की दिशा मजबूत हुई।

25. शांति के माध्यम से भारत का परमाणु पुनर्स्थापन

असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक जवाबदेही और नियामक ढांचे के तहत निजी और विदेशी भागीदारी के लिए खोलने की सोच सामने आई। इससे ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ आधारभूत बिजली और दीर्घकालिक क्षमता विस्तार की दिशा में नया मानक स्थापित करने का प्रयास हुआ।

25 विचार जिन्होंने बदली दिशा और प्रक्रियाएं

25 वर्ष की सुशासन यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे विचार और संस्थागत पहल को राज्य से लेकर राष्ट्र तक सामने रखा, जो केवल योजनाएं नहीं बनीं, बल्कि कार्यशैली के तौर-तरीकों में बदलाव की दिशा निर्धारित कर दी। इन पहल में व्यवस्था को केवल चलाने का नहीं, बल्कि उसे संस्थागत रूप से बदलना लक्ष्य रहा है। इससे कहीं जिम्मेदारी सरकार से समुदाय तक पहुंची, कहीं नागरिक नीति प्रक्रिया के भागीदार बने, कहीं तकनीक को सार्वजनिक आधार बनाया गया और कहीं राष्ट्रीय प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मंच मिला।

1. **जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन (डब्ल्यूएएसएमओ), गुजरात (2003):** ग्रामीण जल योजनाओं की जिम्मेदारी सरकार से गांवों तक पहुंची। पानी समितियों को योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मिली। महिलाओं की भागीदारी ने इसे सामुदायिक मॉडल बनाया, जिसे बाद में जल जीवन मिशन में भी अपनाया गया।

2. **एसडीएमए (2003):** भुज भूकंप के बाद गुजरात ने आपदा प्रबंधन को केवल राहत तक सीमित रखने के बजाय तैयारी, क्षमता निर्माण और जोखिम कम करने के लिए कानूनी संस्थागत ढांचा बनाया। 2005 में इसी दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनी।

3. **विशेष क्षेत्रों के विश्वविद्यालय:** फोरेंसिक विज्ञान, आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा, खेल, शिक्षा, संस्कृत और योग जैसे क्षेत्रों के लिए अलग संस्थान और विश्वविद्यालय बनाए गए। इससे विशेष जरूरतों के अनुरूप प्रतिभा तैयार करने का संस्थागत आधार बना।

4. **गिफ्ट सिटी (2007):** भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक ग्रीनफील्ड केंद्र विकसित किया गया। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था और एकल नियामक के जरिए भारत में वैश्विक वित्तीय गतिविधियों के लिए नया मंच तैयार हुआ।

5. **अलग जलवायु परिवर्तन विभाग (2009):** जलवायु परिवर्तन को स्थायी सरकारी जिम्मेदारी बनाया गया। नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, उत्सर्जन में कमी और जलवायु-अनुकूल योजना के लिए अलग बजट और प्रशासनिक व्यवस्था बनी।

6. **माय गॉव (2014):** नागरिकों को नीति निर्माण में सुझाव, चर्चा, सर्वे और आइडिया कैंपेन के जरिए भागीदारी का स्थायी डिजिटल मंच मिला। जनता की भूमिका दर्शक से भागीदार की ओर बढ़ी।

7. **नीति आयोग (2015):** योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली। राज्यों के साथ संवाद, स्टेट सपोर्ट मिशन और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के जरिए नीति निर्माण को परिणामों और सहकारी संघवाद से जोड़ा गया।

8. **प्रगति (2015):** अटकी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक ऐसी व्यवस्था बनी, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारी एक साथ जवाबदेह होते हैं। परियोजनाओं की प्रगति और समस्याएं एक ही मंच पर दिखाई देने लगीं।

9. **इंटरनेशनल सोलर अलायंस (2015):** भारत और फ्रांस की पहल से सौर ऊर्जा के लिए संधि-आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन बना। साझा खरीद, मानक, परियोजना तैयारी और वित्तपोषण के जरिए सौर ऊर्जा को वैश्विक सहयोग का आधार मिला।

10. **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (2016):** आधार, यूपीआई और अकाउंट एग्रीगेटर जैसे खुले डिजिटल ढांचे तैयार किए गए, जिन पर बैंक, स्टार्टअप और सरकारें नई सेवाएं बना सकती हैं। सार्वजनिक डिजिटल सुविधाएं एक साझा आधार बन गईं।

11. **जीईएम (2016):** सरकारी खरीद को एक साझा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर कीमतों, उत्पादों और विक्रेताओं की पारदर्शिता बढ़ाई गई। खरीद व्यवस्था को बिचौलियों और सीमित प्रतिस्पर्धा से निकालकर खुले डिजिटल बाजार की ओर ले जाया गया।

12. **दिवाला और दिवालियापन संहिता (2016)** डिफॉल्ट से जुड़ी लंबी और बिखरी प्रक्रियाओं की जगह समयबद्ध और लेनदार-नियंत्रित व्यवस्था लाई गई। इससे क्रेडिट अनुशासन को संस्थागत आधार मिला।

13. **अटल इनोवेशन मिशन (2016):** नवाचार को स्कूल स्तर तक पहुंचाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब और स्टार्टअप के लिए अटल इनक्यूबेशन केंद्र बनाए गए। इनोवेशन की सोच को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला। अब तक 10,000 लैब बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में और आधे से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हैं।

14. **रेरा (2016):** रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिला। परियोजना पंजीकरण, अलग खाते में खरीदारों की राशि और विवाद निपटान की व्यवस्था ने जवाबदेही बढ़ाई।

15. **जीएसटी परिषद (2016):** केंद्र और राज्यों को एक संवैधानिक संस्था के माध्यम से साझा कर व्यवस्था तय करने का मंच मिला। जीएसटी ने अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों की जगह एक साझा राष्ट्रीय बाजार की दिशा में बदलाव किया।

16. **ओबीसी संवैधानिक आयोग (2018):** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उसकी संस्थागत स्थिति मजबूत की गई। इससे आबादी के एक बड़े हिस्से को स्थायी संस्थागत आवाज मिली।

17. **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (2019):** तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए सीडीएस का पद और सैन्य मामलों का विभाग बनाया गया। लंबे समय से सुझाए जा रहे संयुक्त सैन्य ढांचे को संस्थागत रूप मिला।

18. **सीडीआरआई (2019):** भारत की पहल पर आपदा-प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बना। शोध, तकनीकी सहयोग और मजबूत निर्माण मानकों के जरिए प्रतिरोधी क्षमता को साझा वैश्विक प्राथमिकता बनाया गया।

19. **IN-SPACe अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा (2020):** अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए सिंगल-विंडो व्यवस्था बनी। इससे निजी क्षेत्र को लॉन्च, सैटेलाइट, परीक्षण सुविधाओं और अंतरिक्ष सेवाओं में आगे बढ़ने का संस्थागत रास्ता मिला।

20. मिशन कर्मयोगी–iGOT (2020): सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को पद और वरिष्ठता आधारित व्यवस्था से निकालकर लगातार क्षमता-आधारित सीखने से जोड़ा गया। अधिकारियों को उनके काम के अनुरूप डिजिटल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

21. सहकारिता मंत्रालय (2021): सहकारी क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय बनाकर राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस, बहु-राज्यीय सहकारी ढांचे और पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण जैसी पहलों को संस्थागत आधार दिया गया।

22. अग्निपथ योजना (2022)

अग्निवीर व्यवस्था के जरिए जवानों की भर्ती और सेवा संरचना में बदलाव किया गया। चार वर्ष की सेवा, चयनित जवानों को आगे बनाए रखने और अन्य अवसरों के प्रावधान के जरिए सेना को लंबे समय के लिए अधिक युवा बनाने की दिशा तय हुई।

23. मेरा युवा भारत (2023)

युवाओं के लिए कौशल, स्वयंसेवा, नेतृत्व और स्थानीय विकास को साझा मंच पर लाया गया। पंजीकरण और साझा डेटाबेस के जरिए युवाओं की भागीदारी को निरंतर स्वरूप मिला।

24. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (2023)

सात बिग कैट्स संरक्षण के लिए साझा अंतरराष्ट्रीय मंच बनाया गया। शोध, निगरानी, अवैध शिकार रोकने और अनुभव साझा करने के जरिए वन्यजीव संरक्षण को संस्थागत सहयोग मिला।

25. ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (2023)

भारत, ब्राजील और अमेरिका की पहल से जैव-ईंधन के लिए साझा अंतरराष्ट्रीय मंच बना। साझा मानकों, तकनीक और व्यापार के जरिए वैश्विक ऊर्जा बदलाव को गति देने का प्रयास हुआ।

> *पॉलिसी और गवर्नेंस से जुड़े इकोसिस्टम में मुझे अब 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जिन्होंने भी मुझे इन वर्षों में देखा है, वो जानते हैं, मोदी एक पड़ाव पर पहुंचकर, जश्न मनाकर संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। जब एक लक्ष्य प्राप्त होता है, तो मैं उससे भी बड़े लक्ष्य की तैयारी में जुट जाता हूं।*
>
> **–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

मुंबई में 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' का उद्घाटन

यूपीआई... एक सभ्यता की कहानी

भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है। इसका एक बड़ा चैंपियन यूपीआई है। यूपीआई केवल एक टेक स्टोरी नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल स्टोरी यानी एक सभ्यता की पूरी कहानी बयां करता है। 8 सितंबर को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2026 के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज फिनटेक बाजार का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेमेंट्स का है लेकिन अब हमें, यहां से नेक्स्ट लेवल पर है जाना...

टेक्नोलॉजी, इंक्लूजन का सबसे प्रभावी टूल है और यूपीआई ने यह करके दिखाया है। जब फिनटेक की बात आती है तो इसका यूनीक फीचर ही वहां पहुंचने का होना चाहिए, जहां ट्रेडिशनल मॉडल नहीं पहुंच पाए। जहां पारंपरिक बैंक नहीं पहुंच पाए, जहां बैंक ब्रांच नहीं पहुंच पाई। यूपीआई ने बैंकिंग व्यवस्था को उस स्थान, उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब फिनटेक मार्केट में, पेमेंट्स के साथ-साथ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए, इंश्योरेंस का हिस्सा बढ़ना चाहिए, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और पेंशन का हिस्सा बढ़ना चाहिए।

यूपीआई ने 25 अगस्त को ही 10 साल पूरे किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, तो कुछ लोगों को यह असंभव लगता था। लेकिन आज 10 वर्ष बाद देखिए, वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं।

भारत की प्रगति से दुनिया को मिला नया भरोसा

दुनिया संघर्षों और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऊर्जा और कमोडिटीज की आपूर्ति चेन पर दबाव एवं ट्रेड को लेकर भी तनाव है। ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई हैं। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा है। इसमें जब भारत 7.8% से ग्रो करता है, तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरीन रेटिंग्स भी है। हाल में ही, जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरीन रेटिंग्स को A-कैटेगरी में अपग्रेड किया है। यह अवसर तीन दशक के बाद आया है। यह दिखाता है कि भारत के ग्रोथ मोमेंटम, मैक्रो-इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बीते वर्षों में किए गए हैं, उन सब को लेकर दुनिया कितनी आश्वस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं फिर कहूंगा कि भारत की ये रिफॉर्म एक्सप्रेस और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी।

अगस्त महीने में ही यूपीआई से 24 सौ करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए हैं। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है।

डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता, स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम्स हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

फिनटेक कंपनियों के लिए पीएम मोदी का टास्क...

21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। **Agentic AI**, **Tokenisation**, **Quantum**, ऐसी **Technologies** फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। अब चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इंपैक्ट में कैसे बदलें। पीएम मोदी ने कहा फिनटेक कंपनियां मिलकर कुछ टास्क रखें, मेरे कुछ सुझाव हैं - अगर इन कसौटियों पर खुद को कसेंगे, तो भारत का **Fintech Sector** असंख्य **possibilities** का गेटवे बन सकता है...

1. भारत में **cyber security** को टॉप नॉच बनाना है।
2. इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए।
3. एक मजबूत, फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है।
4. एक, फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए। जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।

पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

एक पड़ाव पर पहुंचकर संतुष्ट होने वालों में नहीं हैं पीएम मोदी

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पॉलिसी और गवर्नेंस से जुड़े इकोसिस्टम में मुझे अब 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जिन्होंने भी मुझे इन वर्षों में देखा है, वो जानते हैं कि मैं एक पड़ाव पर पहुंचकर, जश्न मनाकर संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं। जब एक लक्ष्य प्राप्त होता है तो मैं उससे भी बड़े लक्ष्य की तैयारी में जुट जाता हूं। उन्होंने कहा कि आज हमारा यूपीआई कई देशों में पहुंचा है लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। अब उन देशों के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ना हमारा अगला लक्ष्य होना चाहिए। सिंगापुर के साथ हम यह कर चुके हैं।

8 से 11 सितंबर 2026 तक मुंबई में आयोजित जीएफएफ

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2026 का सातवां संस्करण 8 से 11 सितंबर 2026 तक मुंबई में आयोजित किया गया। 2020 से, जीएफएफ एक अंतरराष्ट्रीय विचार नेतृत्व मंच के रूप में उभरा है जो नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक कंपनियों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों को वित्त के भविष्य को आकार देने पर विचार-विमर्श करने के लिए आपस में जोड़ता है।

'फ्रेट कॉरिडोर' विकसित होते भारत की जीवनरेखा

केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक देश को 'विकसित भारत' बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इस लक्ष्य को पाने में सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है। यही वजह है कि केंद्र की वर्तमान सरकार देश के हर हिस्से को तेजी से विकसित कर रही है। इसी कड़ी में गुजरात के बड़ोदरा में 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट, रेल लाइन, सड़क मार्ग, बिजली, आवास और जलापूर्ति से जुड़ी 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन...

विकसित भारत के लिए देश को ऐसी कनेक्टिविटी चहिए, जो सुगम भी हो आज की जरुरतों के अनुसार भी हो। इसी कड़ी में बड़ोदरा से 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हुआ। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए वर्ष 2004 में विचार शुरू हुआ, 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई लेकिन वर्ष 2014 तक इससे जुड़ी फाइल यहां से वहां होती रहीं। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तब जाकर इस कॉरिडोर का काम पूरा हो पाया। आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश के व्यापार-कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है।

2014 के बाद अब तक भारत में 50 हजार आधुनिक रेल कोच बनाए गए हैं। ढ़ाई लाख रेलवे वैगन रेल में जोड़े गए हैं।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। आज पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर्स पर हर रोज 430 से ज्यादा मालगाड़ियां चलती हैं। पहले जो मालगाड़ी, साढ़े 6 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करती थी और अब वही मालगाड़ी आधे से भी कम समय में 100 किलोमीटर का सफर

उद्घाटन और शिलान्यास...

- वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई।
- छोटा उदेपुर-धार परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई जोबत-टांडा रोड नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित।
- एनएच-48 के वडोदरा-सूरत खंड पर सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कंदारी चौकड़ी और लुवारा पाटिया में छह लेन के फ्लाईओवर का उद्घाटन।
- 1,780 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला।
- 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला।
- लगभग 2,600 करोड़ रुपये की गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

'झूठ की गूंज' से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर्स पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।

तय कर लेगी। जिस जगह पर ट्रक से सामान भेजने में सामान्य तौर पर 30 घंटे लगते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर यही दूरी 10-12 घंटे में पूरी हो जाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने विकसित भारत की जिन सप्तधाराओं का विजन रखा है, उनमें एक धारा मैन्युफैक्चरिंग की भी है। अब भारत चिप से लेकर शिप तक, निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानि पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। भारत में पीवी मॉड्यूल बनने शुरु हो गए हैं, जिसकी वजह से आज भारत इसमें 200 गीगावॉट से ज्यादा की कैपेसिटी विकसित कर चुके हैं। देश में 55 लाख परिवार अपने छत पर, टेरेस पर सोलर प्लांट लगा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एआई में दुनिया के सामने सुपर पावर बनना है, तो देश को उसकी तैयारी, उसका इकोसिस्टम भी बनाना होगा। यही काम भारत ग्राउंड पर कर रहा है। तभी किसी देश से यूरेनियम के लिए समझौते हो रहे हैं, किसी से क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर समझौते किए जा रहे हैं। ये सारी मेहनत देश के युवाओं का फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए की जा रही है। दुनिया की जरूरतें बदल रही हैं और इसी प्रकार हमारी पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके भी बदल रहे हैं। इसीलिए, भारत अपनी शिक्षा नीति, शिक्षण और ट्रेनिंग के संस्थानों को नए रूप में ढाल रहा है।

फ्रेट कॉरिडोर की खासियत

जवाहर लाल नेहरु पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीटी) मुंबई, से वड़ोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है। यानि डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वड़ोदरा चला आया। 326 किलोमीटर लंबे इस गलियारे के तीनों खंडों को 20,700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को पीएम मोदी का मंत्र

असली ताकत...

ज्ञान से जागरूकता और जागरूकता से बदलाव

शिक्षक सिर्फ किताबों का पाठ नहीं पढ़ाते, वे जिंदगी को समझना और आगे बढ़ना सिखाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर 5 सितंबर को संवाद कर उनके अनुभवों, नवाचारों और बच्चों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन में शिक्षकों की भूमिका होती जा रही है और भी महत्वपूर्ण...

बच्चों की प्रतिभा पहचानने से लेकर उनकी जिज्ञासा, रचनात्मकता और बचपन को संजोने तक, एक शिक्षक की भूमिका कक्षा से कहीं आगे है। यही कारण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से मिले तो उन्होंने कहा कि बचपन की मासूमियत को सुरक्षित रखना एक महत्वपूर्ण भूमिका है और शिक्षक यह भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में एक समान मूल स्वभाव और जिज्ञासा होती है। यदि शिक्षक इस जिज्ञासा को बढ़ावा और उचित दिशा दें तो वे उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

समय पर मार्गदर्शन दे सकते हैं शिक्षक

शिक्षक का काम सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं, बचपन को सही दिशा देना भी है। पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस पर बच्चों की जिंदगी को कक्षा से आगे समझने की अहमियत पर बात की, खासकर बढ़ते स्क्रीन एडिक्शन और सब्सटांस एब्यूज की चुनौतियों के बीच। खेल, रचनात्मकता और सार्थक जुड़ाव बच्चों में बेहतर आदतें और स्वस्थ रुचियां विकसित कर सकते हैं। वहीं, एक सजग शिक्षक व्यवहार में आए छोटे बदलावों को पहचानकर समय पर मार्गदर्शन दे सकता है।

बच्चों में श्रम की गरिमा जैसे मूल्य विकसित करने में करें सहयोग

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर उन्हें वास्तविक दुनिया के कौशल और कार्य के विभिन्न रूपों से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शिक्षकों से यह भी आग्रह किया कि वे केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित न रहें, बल्कि बच्चों में श्रम की गरिमा जैसे मूल्यों को भी विकसित करने में सहयोग करें।

राष्ट्रपति ने शिक्षकों को प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देशभर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा हमारे संविधान में निहित, 'अवसर की समानता' के आदर्श को कार्यरूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के नगण्य हो जाने की उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से हासिल हो सकी है। उन्होंने इस राष्ट्रीय सफलता के लिए सभी शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के विकास में शैक्षणिक उत्कृष्टता, कौशल विकास और उद्यमिता का बहुत महत्व है। भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के साथ-साथ विश्व के कौशल-केंद्र के रूप में स्थापित करना, हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल है।

बदलाव की शुरुआत

कुछ संवाद सिर्फ बातें नहीं होते, वे बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। एक शिक्षक ने शिक्षा से आगे बढ़कर स्वच्छता और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को समुदायों तक पहुंचाने की अपनी पहल साझा की। पीएम मोदी ने काशी में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अभियान को याद करते हुए बताया कि जागरूकता से अधिक महिलाएं आगे आईं और जांच कराने का साहस दिखाया। यही है एक शिक्षक की असली ताकत, ज्ञान से जागरूकता और जागरूकता से बदलाव।

पब्लिक स्पीकिंग का मंत्र - कॉन्फिडेंस + प्रैक्टिस

एक शिक्षक ने बताया कि अच्छा वक्ता बनने के लिए आत्मविश्वास और लगातार अभ्यास जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तुरंत मजेदार सवाल पूछा - "ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है?" बस फिर क्या था बात पहुंची 'औरा' तक और बातचीत में घुल गई हंसी। कभी-कभी सीखने का सबसे यादगार तरीका होता है - सीख के साथ थोड़ी मुस्कुराहट।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत हुए 82 शिक्षक और शिक्षाविद

इस वर्ष, तीन विभागों से 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 48 शिक्षक, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक/संकाय सदस्य और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं ने अपने शिक्षण अनुभवों और नवाचारों के बारे में बताया। उन्होंने कक्षा शिक्षण को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए अपनाए गए कई रचनात्मक तरीकों को साझा किया।

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

रेल कनेक्टिविटी का विस्तार

ईपीएफओ की वेतन सीमा अब ₹ 25 हजार

राष्ट्र के विकास और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नौ राज्यों में फैली आठ मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से न सिर्फ कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बल्कि 20 करोड़ लीटर तेल आयात में कमी आएगी। इससे रोजगार और पर्यटन के नए अवसर बनेंगे। साथ ही, ईपीएफओ की वेतन सीमा अब 25 हजार रुपये के प्रस्ताव को भी दी गई मंजूरी...

निर्णय : तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में फैली 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी।

प्रभाव : भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपये है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने की योजना है।

- बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।
- ये मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं परिचालन को सुव्यवस्थित और भीड़भाड़ को कम करेंगी।

इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

- अरक्कोनम - रेनिगुंटा तीसरी और चौथी लाइन - 77 किमी
- व्हाइटफील्ड - बांगरपेट तीसरी और चौथी लाइन - 47 किमी
- होसुर - ओमालूर दोहरीकरण मार्ग - 147 किमी
- सलेम - करूर - डिंडीगुल दोहरीकरण - 159 किलोमीटर
- सिकंदराबाद (घाटकेसर) से काजीपेट तक 110 किलोमीटर की मल्टी ट्रैकिंग

"

10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली 5 बड़ी रेलवे परियोजनाएं। दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी। लाखों लोगों को लाभ होगा। कैबिनेट के निर्णय से यात्रियों की तेजी से आवाजाही, मजबूत कनेक्टिविटी और माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता सुनिश्चित होगी।

– नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

निर्णय : पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करने वाली तीन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी।

प्रभाव : भारतीय रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपये है। इन्हें 2029-30 तक पूरा करने की योजना है।

- बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल की परिचालनगत दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।
- इन बहु-ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन सुव्यवस्थित होगा और भीड़भाड़ में कमी आएगी।
- प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 4,790 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिनकी आबादी लगभग 56 लाख है।
- प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क में सुधार होगा

इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

1. खड़गपुर-झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी लाइन
2. कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन
3. बिलासपुर (उसलापुर) - पेंड्रा रोड तीसरी लाइन

51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा लाभ

निर्णय : ईपीएफओ वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी।

प्रभाव : यह फैसला औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और भारत के दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा विजन को आगे बढ़ाता है। यह अनुमोदन एक समावेशी, सुदृढशीलता और भविष्य के लिए तैयार सामाजिक सुरक्षा संरचना के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास, बढ़ती मजदूरी और औपचारिक रोजगार के विस्तार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा आगे बढ़े, क्योंकि देश विकसित भारत@2047 की ओर बढ़ रहा है।

- यह निर्णय 17 सितंबर 2026, विश्वकर्मा दिवस एवं सेवा दिवस के अवसर पर लागू हो गया।
- कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड सेविंग्स,पेंशन और इंशोरेंस प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा।
- लेबर कोड के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में यह बड़ा कदम है।
- सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार के औपचारिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
- 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद।
- सरकार के मौजूदा 10,250 करोड़ रुपये वार्षिक सरकारी खर्च के मुकाबले अब हर साल करीब 11,339 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
- पांच वर्षों में अनुमानित व्यय लगभग 56,696 करोड़ रुपये है।
- ईपीएफओ वेतन सीमा 2004 से 2014 तक के दशक में अपरिवर्तित रही, सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था।
- मंजूरी से अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
- कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन के लिए होने वाले अनिवार्य योगदान तथा पेंशन योग्य वेतन को उनके मौजूदा वेतन के अनुसार तय करने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

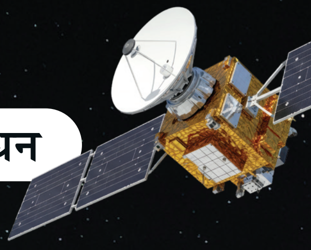

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन

स्पेस एक्सप्लोरेशन का मंत्र टकराव नहीं सहयोग

मनुष्यों की कल्पना को सदियों से प्रेरित करने वाला अंतरिक्ष आज पृथ्वी पर, जलवायु और फसलों से लेकर महासागरों और समुदायों तक जीवन को आकार दे रहा है। संभावनाओं से भरे अंतरिक्ष पर बात करने के लिए पेरिस में 10 सितंबर को पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष की संभावनाएं अनंत हैं और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है...

भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम् के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस भावना को अब पृथ्वी से परे भी ले जाना होगा। हम अंतरराष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ अंतरिक्ष कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिक डेटा का पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ जनहित में उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे ऑर्बिट में भीड़भाड़ बढ़ती जा रही हैं, प्रौद्योगिकियां अधिक विकसित हो रही हैं और संबंधित देशों की संख्या बढ़ रही है, हमारे विकल्प निश्चित रूप से स्पष्ट होने चाहिए। संघर्ष की जगह सहयोग और अल्पकालिक लाभ की जगह स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रहा है भारत

- चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बनाया।
- आदित्य-एल1 सूर्य के रहस्यों को उजागर कर रहा है। पिछले वर्ष, एक भारतीय ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया।
- भविष्य में, हमारा लक्ष्य 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।
- 34 देशों के 430 से अधिक उपग्रह भारतीय रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं।
- इसरो की प्रौद्योगिकियां और साझेदारियां न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी।

> *हम सब मिलकर समस्त मानवता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष की खोज करेंगे, मिलकर नवाचार करेंगे और मिलकर अंतरिक्ष की रक्षा करेंगे।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

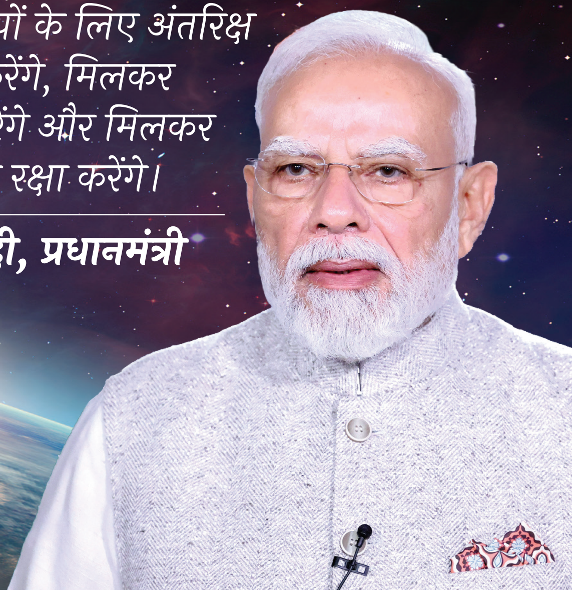

'नशामुक्त भारत'

का संकल्प 2029 तक होगा साकार

नारकोटिक्स एक ऐसा अपराध है जो आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है। साथ ही इससे अर्जित कमाई का उपयोग आतंकवाद के लिए भी होता है। नारको-टेरर का मॉड्यूल दुनिया के कई देशों में सक्रिय है। पूरी दुनिया आज इस समस्या से जूझ रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने 2019 से इस पर नकेल कसने की ठोस व्यवस्था की। और अब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 सितंबर को गोवा की राजधानी पणजी में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2029 तक 'नशामुक्त भारत' का संकल्प करेंगे साकार...

देश भर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में वर्ष 2026 से 2029 तक के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इस रोडमैप के अंतर्गत सभी संबंधित विभागों तथा सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर भारत के गांव-गांव और शहर-शहर को नारकोटिक्स से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। पणजी में नारकोटिक्स नियंत्रण पर एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले यह लड़ाई टुकड़ों-टुकड़ों में लड़ी जाती थी। छोटी जब्तियां कर एवं छोटे आरोपियों को पकड़कर संतोष कर लिया जाता था। लेकिन 2019 से इस विषय को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बनाया।

नशे के खिलाफ लड़ाई फाइलों और अलग-अलग एजेंसियों की कार्रवाई से निकलकर अब राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित और सतत अभियान बन गई है। देश से जैसे नक्सलवाद खत्म हुआ, वैसे ही ड्रग्स की समस्या खत्म करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब ड्रग्स की छोटी-सी पुड़िया भी पकड़ी जाती है तो यह देखा जाता है कि वह देश में कहां से आई।

रोडमैप चार स्तंभों पर आधारित : नशा-मुक्त भारत का रोडमैप चार स्तंभों पर आधारित- इंटेलिजेंस एवं ऑपरेशन आधारित एन्फोर्समेंट, प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स नियंत्रण, डिमांड एवं हार्म रिडक्शन और क्षमता निर्माण एवं समन्वय।

तीन वर्षीय रोडमैप : 'नशामुक्त भारत' बनाने के लिए जुलाई 2026 से जुलाई 2029 तक का तीन वर्षीय रोडमैप तैयार है।

ड्रग्स की जब्ती : वर्ष 2004-14 तक 40 हजार करोड़ रुपये के 26 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त हुए, जबकि 2014-2026 तक 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपये के 1 करोड़ 19 लाख किलोग्राम से अधिक ड्रग्स की जब्ती हुई।

शपथ दिलाई : 'नशामुक्त भारत' अभियान के तहत 25 करोड़ नागरिकों से संपर्क कर शपथ दिलाई गई। 5 लाख 70 हजार नागरिकों को नशामुक्त किया गया।

नशामुक्ति केंद्रों की संख्या : सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन मिलकर केंद्रों की संख्या 3 गुना कर रही है। 1,751 किया जा रहा है।

अभियान : भगोड़ों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा; आर्थिक अपराध, आतंकवाद, नारकोटिक्स और गैंगवार में लिप्त भगोड़े भारत की अदालतों में लाए गए।

संकल्प : शिक्षा, युवा एवं खेल मंत्रालय तथा शिक्षण संस्थान, शिक्षा संस्थानों को ड्रग-फ्री बनाने का संकल्प ले रहे हैं।

नशामुक्ति मित्र : एनसीसी, एनएसएस और **My Bharat** के माध्यम से लाखों 'नशामुक्ति मित्र' तैयार किए जाएंगे।

नई अवधारणा : केंद्र सरकार के बॉटम-टू-टॉप और टॉप-टू-बॉटम अप्रोच से जांच की नई अवधारणा अपनाई गई। वित्तीय जांच और **PIT-NDPS** पर विशेष जोर।

पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर का लोकार्पण

भारत की प्राचीन प्रतिभा, फ्रांस की आधुनिक इंजीनियरिंग का संगम

फ्रांस की राजधानी पेरिस में 6 सितंबर को भव्य स्वामीनारायण मंदिर का लोकार्पण हुआ जो भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों का नया युग स्तंभ बन गया। पूज्य संत जनों और सनातन परंपरा के श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ इस लोकार्पण का मंच 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भाव का मंच भी बन गया। इस मंदिर के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मंदिर है 'मेड इन इंडिया' और 'बिल्ट इन फ्रांस'...

जब अलग-अलग देश में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ-साथ ही जाते हैं। भारत का विचार कहता है 'समानं मनः सह चित्तमेषाम्' अर्थात हमारे मन समान हों और हमारे हृदय साथ जुड़ें। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं।

स्वामीनारायण मंदिर हमेशा से भक्ति के साथ-साथ सेवा का माध्यम भी रहे हैं और यह मंदिर भी सेवा भाव का वैसा ही केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यहां से भारतीय संस्कृति के जो स्वर निकलेंगे, उनका लाभ पूरे यूरोप में लोगों को मिलेगा। भविष्य में मुझे जब भी समय मिलेगा, मैं इस मंदिर में दर्शन करने का प्रयास अवश्य करूंगा।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सहयोग और संभावनाओं का प्रतीक बनकर उभरेगा मंदिर

इन दिनों, भारत फ्रांस संयुक्त उपक्रम की संभावनाओं पर बातें होती हैं। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। यह मंदिर 'मेड इन इंडिया' है और 'बिल्ट इन फ्रांस' है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा, फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ी है और पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इसलिए, मैं आशा करता हूं, यह मंदिर भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।

विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं भारत और फ्रांस

भारत और फ्रांस, दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी, एआई और रक्षा से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। दोनों देश, वर्ष 2026 को भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत-फ्रांस की ये रणनीतिक साझेदारी इसलिए भी खास है, क्योंकि यह पुराने सांस्कृतिक-राजनैतिक संबंधों की मजबूत बुनियाद पर टिकी है। इतिहास गवाह है, फ्रांस में भारतीय सैनिकों का बलिदान आज भी मन-मंदिर में जीवित है। भाषा से जुड़े विषयों में रुचि रखने वाले लोग यह भी जानते हैं कि फ्रेंच स्कॉलर्स ने संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाई है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पर रोमां रोलां की लेखनी दोनों समाज को और करीब लाई। पेरिस से पुडुचेरी के अरबिंदो आश्रम तक 'द मदर' की आध्यात्मिक यात्रा ने कितने ही भारतीय और फ्रेंच साधकों को प्रेरित किया।

दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का एक नया अध्याय

दशकों पहले श्रील प्रभुपाद स्वामी भी फ्रांस आए थे। इस्कॉन के जरिए भारत फ्रांस के बीच आध्यात्मिक संबंधों का नया अध्याय उन्होंने शुरू किया था। आज योग भी भारत-फ्रांस के पीपुल टू पीपल कनेक्ट का एक माध्यम बन चुका है। 'इंटरनेशनल योगा डे' पर एफिल टॉवर के सामने से आने वाली तस्वीरें फ्रांस में योग की लोकप्रियता का उदाहरण बनती हैं। अब **BAPS** के इस भव्य मंदिर के जरिए, दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है।

> ***"यह मंदिर फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।"***
>
> ***–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री***

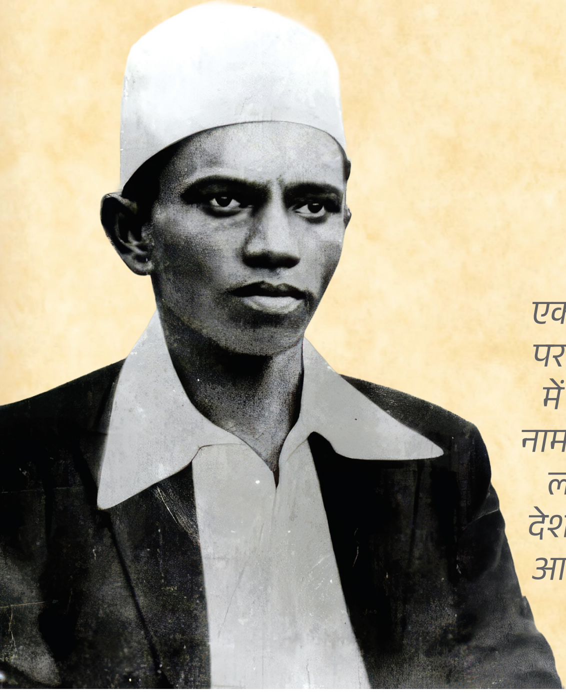

जिन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया राष्ट्रीय ध्वज

एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने अंग्रेजों के आगे राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) जमीन पर गिरने नहीं दिया। राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में थामे रखा, भले ही इस ध्वज रक्षा में उनकी जान चली गई। प्राण न्यौछावर करने वाले इस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है तिरुप्पुर कुमारन। ब्रिटिश सरकार ने उस समय भारतीय ध्वज पर प्रतिबंध लगा रखा था। उनके इस बलिदान ने केवल विरोध का काम नहीं था, बल्कि देशवासियों में एकता, सम्मान और साहस की भावना जगाने का आह्वान भी था। आज भी तिरुप्पुर कुमारन का यह साहस नागरिकों को निरंतर करता है प्रेरित...

जन्म : 4 अक्टूबर, 1904 ■ मृत्यु : 11 जनवरी, 1932

स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी तिरुप्पुर कुमारन का जन्म 4 अक्टूबर, 1904 को चेन्नीमलाई में हुआ था जो अभी तमिलनाडु के इरोड में स्थित है। जब देश में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो कुमारन भी उससे प्रभावित हुए। महात्मा गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने आजादी के आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया। 1932 में जब गांधीजी ने बॉम्बे में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में लोग राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) लेकर चल रहे थे, जिस पर उस समय पाबंदी लगी हुई थी। वे इसे सम्मान और विरोध, दोनों के तौर पर ले जा रहे थे। झंडा थामने वाले प्रदर्शनकारियों में तिरुप्पुर कुमारन भी शामिल थे। जब ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो कुमारन वहां से नहीं हटे। पुलिस ने कुमारन समेत प्रदर्शनकारियों की बुरी तरह पिटाई की। ऐसे में वे गिर तो गए, लेकिन उन्होंने झंडे को जमीन से नहीं छूने दिया। 11 जनवरी, 1932 को गंभीर चोट के कारण इस 27 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया।

'कोडी काथा कुमारन' यानी 'तिरंगे की रक्षा करने वाले कुमारन' के नाम से पहचान रखने वाले तिरुप्पुर कुमारन की विरासत भारत माता के प्रति अटूट निष्ठा और अन्याय के विरुद्ध अडिग संकल्प का संगम है। अंतिम क्षणों में भी तिरंगे को मजबूती से थामे रखने का उनका जज्बा हमें याद दिलाता है कि आजादी बेमिसाल साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम से हासिल की गई थी। उनकी वीर स्मृति हर पीढ़ी को राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करने, मुश्किल से मिली आजादी का सम्मान करने और पूरी निष्ठा व त्याग के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है।

पदभार ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु की अपनी पहली यात्रा पर कोयंबटूर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने तिरुप्पुर कुमारन प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान विभूति - तिरुप्पुर कुमारन को उनके स्मृति दिवस पर याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दिन हम भारत माता के महान सपूत तिरुप्पुर कुमारन को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। वे महान राज्य तमिलनाडु से थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तिरुप्पुर कुमारन राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए शहीद हुए और इस प्रकार दिखाया कि अदम्य साहस और निःस्वार्थ बलिदान क्या होता है। इस महान विभूति के प्रयास हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। हमें उन अनगिनत लोगों के संघर्षों और कष्टों की याद दिलाते हैं जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित की। ईश्वर करे कि उनका योगदान हम सभी को राष्ट्र के विकास और एकता के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करता रहे। ■

PMO India
@PMOIndia

आज विश्व एक बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है।

दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।

Food, fuel या supply chains, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है।

इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की economy ने अपनी गति बनाए रखी है।

पिछले quarter में हमने 7.8 प्रतिशत की growth दर्ज की है।

आज भारत की growth story दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है: PM @narendramodi

Rajnath Singh
@rajnathsingh

आत्मनिर्भरता केवल हथियार और उपकरण बनाने तक सीमित नहीं है। यह हमारे चरित्र, सोच और आत्मविश्वास का हिस्सा होनी चाहिए। जिस देश के पास अपनी टेक्नोलॉजी होती है, उसके पास अपना भविष्य तय करने की ताकत भी होती है।

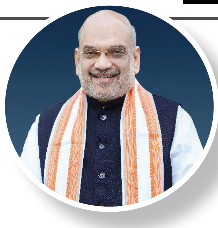

Amit Shah
@AmitShah

लोकतंत्र में परफॉर्मेंस और डिलीवरी पर मिला जनादेश ही सबसे बड़ा प्रमाणपत्र होता है, और जनता ने 25 वर्षों तक मोदी जी को यह जनादेश दिया है।
#SevaSankalpAbhiyan

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

A moment to shape the future of the Global South!

🇮🇳India is all set to host the XVIII BRICS Summit—bringing together 11 nations, 49% of the world's population and 40% of global GDP.

#BRICS2026 #BRICSIndia2026

Shivraj Singh Chouhan
@ChouhanShivraj

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसान के हित में लगातार काम कर रही है। किसान दिन-रात मेहनत करता है, ऐसे में अगर उसे नकली या घटिया बीज और खाद मिल जाए तो उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

इसीलिए नकली और अमानक बीज के खिलाफ कड़ा कानून लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 सितंबर को देशभर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्रस्तावित सीड एक्ट पर उनकी बात सुनेंगे और उनके सुझाव लेंगे।

किसान को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले और नकली बीज बेचकर उसे नुकसान पहुँचाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो; हमारा यही संकल्प है।

Kiren Rijiju
@KirenRijiju

Hello India! भारत से जुड़ रही दुनिया... !

उज़्बेकिस्तान से दक्षिण अफ्रीका और बेलारूस से वियतनाम व युगांडा तक, हर आवाज़ में भारत के प्रति अपनापन और सम्मान देखने को मिला। नई दिल्ली में BRICS के मंच पर विभिन्न देशों के साथ 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना की सुंदर झलक दिखाई दी।

भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत : ब्रिक्स का दिल्ली घोषणापत्र जारी...पहलगाम आतंकी हमले की एक सुर में निंदा

युद्ध-टैरिफ थोपने व आतंक के खिलाफ एकजुट

अमेरिका और इस्राइल का नाम लिए बगैर फलस्तीन के हक की बात भी

डब्ल्यूटीओ के नियम माने जाएं : जबरन लगाए आर्थिक प्रतिबंध स्वीकार्य नहीं

किसने क्या कहा...

अब दुनिया के नियम ब्रिक्स देश बनाएं : मोदी

केंद्र ने कैबिनेट बैठक में आठ रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी

फैसला : दबाव वाले रेलवे कॉरिडोर चार लेन के होंगे

प्रौद्योगिकी व दुर्लभ खनिजों का हथियारों के तौर पर इस्तेमाल खतरनाक : मोदी

पीएम मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं, राष्ट्र के प्रगति की कामना की

'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच विराजे भगवान श्री गणेश

20 साल का हुआ 21 देशों का ब्रिक्स

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती
15 अक्टूबर पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन

जिनके शब्दों-विचारों में दिखा भविष्य का भारत

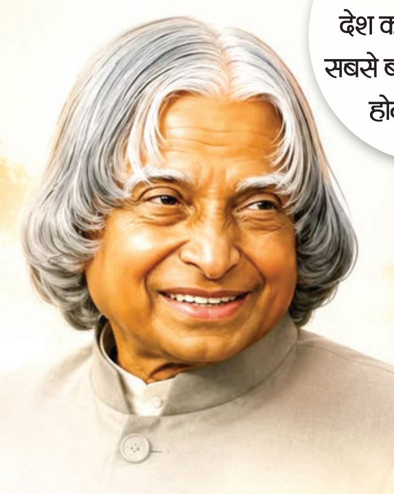

21वीं सदी में ऊर्जा और पानी की बढ़ती मांग हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली बड़ी चुनौतियों में शामिल होगी।

अब समय आ गया है कि नदियों को जोड़ने की योजना को पूरी गंभीरता और तेजी के साथ लागू किया जाए।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता देश की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

हमारा लक्ष्य ऐसा देश बनाना होना चाहिए जो केवल समृद्ध और खुशहाल ही न हो, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी हो।

किसी भी बाहरी आक्रमण से हमेशा सुरक्षित रहे। भविष्य में अंतरिक्ष से होने वाली किसी भी आक्रमण गतिविधि से भी देश की रक्षा हो सके।

भविष्य के भारत की तैयारी कैसी हो, चुनौतियों के लिए भारत तैयार रहे। ऊपर लिखे गए शब्द-विचार भारत प्रथम के सिद्धांत के साथ विज्ञान, रक्षा और तकनीकी नवाचारों में राष्ट्र हित की सोच रखने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के हैं। अभी इन सभी विचारों पर देश खूब काम कर रहा है। इंडिया 2020: ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक में भविष्य के भारत के लिए उन्होंने जो विचार रखे, उन्हीं विचारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है अग्रसर...

“ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने देश को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन स्मरण दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और अथक परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। हम उनके द्वारा देखे गए भारत का निर्माण करते रहें... एक ऐसा भारत जो सशक्त, आत्मनिर्भर और करुणामय हो। **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 अक्टूबर, 2026

आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 22 सितंबर 2026, कुल पृष्ठ-64)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित